personally. I am going to sit with the hon. Member, my predecessor, and, take his point of view. My Ministry has already been informed that I am going to interact with some hon. Members of this House, who have volunteered to give us suggestions on rectifying the TRP rating system in this country, and, I will not go back on my words.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, on a lighter note, the influence of the TRP is such that the hon. Minister is referring to this discussion as a 'programme'. You just mentioned it as a 'programme'.

SHRIMATI AMBIKA SONI: It is not part of this. Sir, in all humility, I will take as my guidelines the two recent speeches of the hon. Chairperson of this House, the Vice-President of India. He made a speech on 29th November to the Parliament's Media Advisory Committee, and, then he spoke in the Varghese Memorial Lecture on 28th January. Extracts from his speech have already been quoted by the hon. Members. The hon. Vice-president, the hon. Chairman of this House, spoke of the growth, the mind-boggling growth of different platforms of media, and, in that context, he also drew up what media meant during the freedom struggle, what media meant post- Independence, and, what media has come to mean after the 1990 — Era of liberalisation.

Sir, I would like to end by quoting again another extract from the Vice-President's speech. He said, "The recent practices of leveraging political and economic content in our media for overt and covert revenue generation have the malevolent potential to tarnish our polity and even destabilise the economy." This is how seriously the Government also feels about this whole issue. Let the report come in end of March. I will place it in the House and the hon. Members can then have a structured debate and we can take whatever suggestions that come out.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour.

————————

The House then adjourned for lunch at five minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at seven minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश): मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में अंतिम पृष्ठ की जो पंक्ति है, जिनकी चर्चा मेरे कुछ और मित्रों ने भी की है, वह मुझे सबसे अधिक अच्छी लगी। उन पंक्तियों में आज से लगभग 63 वर्ष पूर्व, 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा कहे गए शब्दों को उद्धृत किया गया है। वह एक संकल्प है देश से गरीबी दूर करने का, अज्ञानता दूर करने का और बराबरी लाने का। उस संकल्प को फिर से याद किया गया। मैं सबसे पहले उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ।

अभिभाषण में बहुत-सी बातों का जिक्र है, उपलब्धियों का जिक्र है। कुछ बातें सराहनीय हैं। जनता को उसका लाभ हुआ है, हो रहा है। मैं उन सराहनीय जनहित की बातों के लिए उनकी सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। लेकिन, मुख्य बात क्या है? जो मूल समस्याएँ देश की हैं और 63 वर्ष पहले जिन बातों के लिए

संकल्प किया गया था, उन बातों के संबंध में क्या हुआ है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या गरीबी दूर हुई है? क्या विषमता दूर हुई है? क्या महँगाई की मार से गरीब बच रहा है? क्या आतंकवाद और माओवाद से किसी प्रकार की मुक्ति देश को मिली है? ये जो बुनियादी समस्याएँ हैं, इन पर क्या हुआ? यह है कसौटी सफलता की और विफलता की। बाकी बहुत-सी बातों की चर्चा है। आखिर संसद ने सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये दिये थे। इतना पैसा दिया था तो खर्च तो होना ही था। Routine के कामों की चर्चा के बारे में पढ़ कर ऐसा लगता है कि जैसे वह सरकार का विज्ञापन हो। इतने करोड़ यहाँ खर्च किया, इतने करोड़ वहाँ खर्च किया। वह routine के कामों की चर्चा है, कोई बहुत बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। कोई और सरकार होती, वह भी यह करती, लेकिन संकल्प का क्या हुआ? बुनियादी समस्याओं का क्या हुआ? प्रश्न यह है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, उस दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो आज गरीबी की दिशा में कुछ नहीं हुआ, यही नहीं है, बल्कि देश की गरीबी बढ़ रही है। आज 28 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और इसी सरकार के विभिन्न विभागों ने 14 रुपए दैनिक की रेखा निश्चित की है, अर्थात एक दिन में 14 रुपए में 28 करोड़ लोग जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। कहां है आपका संकल्प? कहां है गांधी जी का अंत्योदय? 28 करोड़ लोग यदि गरीबी की रेखा से नीचे हैं और Global Hunger Index में जो भूख से पीड़ित देश हैं, उनमें भारत की गणना 68वें स्थान पर है। United Nations Food Programme में कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग आज भारत में रहते हैं, कुपोषण से सबसे ज्यादा बच्चे भारत में मरते हैं।

मैं देख रहा था कि गरीबी दूर करने की दिशा में क्या उपलब्धि है? सच्चाई तो यह है कि गरीबी बढ़ी है और पिछले अधिवेशन में लोक सभा में सरकार ने स्वयं स्वीकार किया था कि गरीबों की संख्या 4 करोड़ 40 लाख बढ़ी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि पिछले एक साल में एक भी व्यक्ति गरीबी की रेखा को पार करके ऊपर नहीं गया, तो फिर कहां है आपका संकल्प? 10 लाख करोड़ रुपया संसद ने आपको दिया, गरीबी दूर करने का संकल्प आपका था, लेकिन गरीबों की संख्या बढ़ी, एक भी व्यक्ति गरीबी की रेखा से उठकर ऊपर नहीं गया। इतना ही नहीं, अमीरी बढ़ गई। मेरे कुछ और मित्रों ने भी ज़िक्र किया है कि आज दुनिया के करोड़पतियों की संख्या में भारत के करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है। भारत के 100 अमीर लोगों की सम्पत्ति पिछले एक साल में 6 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गई। 36 अमीर घरानों के पास 10 लाख करोड़ रुपए हैं। दुनिया के सबसे अमीर बीस लोगों में अमरीका के पांच हैं तो भारत के तीन हैं। देश अमीर हो रहा है और देश गरीब हो रहा है। कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर हो रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा गरीब हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य है देश का। यह एक चमत्कार है कि GDP बढ़ रहा है, अमीरी बढ़ रही है, लेकिन 28 करोड़ लोग झोंपड़ियों में सिसक रहे हैं! यह स्थिति इस देश की है। कारण क्या है? सामाजिक न्याय नहीं हुआ। देश की सम्पत्ति बढ़ी, देश का ऐश्वर्य बढ़ा, GDP बढ़ा, लेकिन वह कुछ हाथों में ही सिमटकर रह गया और बहुत से लोग गरीब हो गए। उपसभाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यदि यही गति सरकार की रही, यदि इसी प्रकार से pro-rich policy, anti-poor policies आपकी रहीं, जिसने कुछ लोगों को कमाई करने का नहीं, लूट का लाइसैंस दिया, तो भारत में गरीबों और भूखे-नंगों की संख्या बहुत बढ़ेगी। एक साल में 100 लोगों की सम्पत्ति 6 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हो गई और आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप संकल्प दोहरा रहे हैं 63 साल पुराना, इन 100 अमीर लोगों की सम्पत्ति अगर 6 लाख करोड़ से बढ़कर 13 लाख करोड़ हुई तो कमाई से नहीं, लूट से हुई और लूट का लाइसैंस किसने दिया? आपने दिया।

मुझे लगता है कि अगर नीतियां और हालात यही रहे तो कुछ दिन बाद भारत में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है और वह चमत्कार यह होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति लोग हिन्दुस्तान में होंगे और दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे-नंगे भी हिन्दुस्तान में होंगे। तब शायद गिन्नीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में आपका नाम आ जाए, तब कौन सा पुरस्कार इस सरकार को देना पड़ेगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि संविधान के अंदर

आर्टिकल 39 में कहा था — Article 39 (c) provides that the operation of economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. सम्पत्ति का कंसन्ट्रेशन नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन 63 वर्ष पहले से लेकर आज तक सम्पत्ति का एकाधिकार हो रहा है, कंसन्ट्रेशन हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष जी, जो गरीबी है और अमीर तथा गरीब के बीच की जो खाई है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। देश की संपत्ति बढ़ रही है, यह खुशी की बात है, लेकिन वह संपत्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो रही है और करोड़ों लोग भूखे-नंगे झोपड़ियों में सिसक रहे हैं, यह खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आज इस देश में अपराध बढ़ रहा है, दिल्ली में सुबह-सुबह अखबार पढ़ने से डर लगता है। सरकार की नाक के नीचे कितने अपराध प्रतिदिन होते हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है, माओवाद बढ़ रहा है। इन अपराधों के बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण गरीबी है, एक बड़ा कारण आर्थिक विषमता है, क्योंकि अगर करोड़ों लोग निराश हैं, हताश हैं, बेरोज़गार हैं, दो वक्त की सूखी रोटी उनको नहीं मिल रही है। किसी पिता की आंखों के सामने अगर उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तो वह मजबूर, हताश कहां जाएगा? वह अपराध के रास्ते पर जा सकता है, वह नक्सलवाद के रास्ते पर जा सकता है। मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा — "Development Challenges in Extremist Affected Areas" इस संबंध में एक Report of an Expert Group to Planning Commission है, इस रिपोर्ट के अंदर दो-तीन जगह, उन विद्वान लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला है, उसे मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। एक जगह उन्होंने कहा है कि:

> "India is, today proudly proclaiming an above nine per cent growth rate and striving to achieve a double digit growth. But it is a matter of common observation that the inequalities between classes, between town and country, and between the upper caste and the under-privileged communities are increasing. That this has potential for tremendous unrest is recognised by all."

उपसभाध्यक्ष जी, विकास हो रहा है, लेकिन भेदभाव बढ़ रहा है, विषमता भी बहुत अधिक बढ़ रही है। इसी रिपोर्ट में से मैं एक और बात quote करना चाहूंगा, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और विचार करने योग्य हैं।

> "The Administration should not have waited for the Naxalite movement to remind it of its obligation towards the people in this matter. But at least now that the reminder has been given, it should begin rectifying its own deficiencies. It should be recognised that such a responsibility would lie upon the Indian State even if the Naxalites were not there, and even in regions where the Naxalite movement does not exit."

इस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलवादी, माओवादी मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण गरीबी है, सबसे बड़ा कारण विषमता है। यह किसने फैलाई? आपने गरीबी दूर करने का संकल्प किया था और आपने विषमता दूर करने का संकल्प किया था, 63 साल के बाद आज सरकार की रिपोर्ट यह कह रही है कि नक्सलवाद, माओवाद का सबसे बड़ा कारण है आर्थिक विषमता। इस रिपोर्ट के अंत में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है—

> "There is no denying that what goes in the name of 'Naxalism' is, to a large extent, a product of collective failure to assure to different segments of society their basic entitlements under the Constitution and other protective legislation."

उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस संकल्प का क्या हुआ, यदि उस संकल्प को आपने पूरा किया होता, तो आज नक्सलवाद इस ढंग से न होता। यह जमीन किसने तैयार की, यह गरीबी की जमीन किसने तैयार की, इसमें भुखमरी की खाद किसने डाली? आज नक्सलवादी उसमें बीज लगाने के लिए आ गए, यदि वे न आते, तो कोई और आता। इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक विषमता है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे कुछ मित्रों ने एक और बात का जिक्र किया है, मैं भी उसका जिक्र करना चाहता हूं कि इस पूरे अभिभाषण में बढ़ती हुई आबादी की समस्या के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज global warming की बात की जा रही है। जनसंख्या बढ़ेगी, तो घर बनेंगे, तो सड़कें बनेंगी, तो गाड़ियां होंगी, तो भीड़-भड़क्का होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जनसंख्या को रोकने की दृष्टि से कोई चिंता सरकार नहीं कर रही है, प्रति वर्ष लगभग 2 करोड़ लोग हमारी आबादी में बढ़ रहे हैं।

चीन के मुकाबले हमारा वृद्धि दर अधिक हो गया है। 2025 तक भारत की आबादी 140 करोड़ हो जाएगी। स्टेशन से लेकर सड़क तक और हर जगह इतना भीड़-भड़क्का दिल्ली में हो रहा है, लेकिन सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री जी इस सवाल पर पहल करे। सभी राजनीतिक दलों को बुलाकर एक National Population Policy बनाइए। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है, वैसे ही हम इस समस्या से अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र करना चाहता हूँ, जिसकी चर्चा इसमें कहीं पर नहीं है। आज भ्रष्टाचार कैंसर की तरह, महामारी की तरह इस देश को अंदर से खोखला कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की बन रही है। हर कदम पर भ्रष्टाचार है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। क्या सरकार ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है या सरकार को भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है? समय सीमा के कारण मैं केवल उसका जिक्र मात्र करूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि निचले स्तर पर 21 हजार करोड़ रुपए का लेन-देन यहां पर होता है, और तो छोड़िए, उपसभाध्यक्ष जी, बिजली, जिस पर नियंत्रण सरकार का Electricity Board करता है, उसमें तीस परसेंट से ज्यादा बिजली चोरी होती है। जो लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की है। इस तरह से इस देश में 27 हजार करोड़ रुपए की बिजली की चोरी होती है। Transparency International की रिपार्ट के मुताबिक दुनिया के 180 देशों को भ्रष्ट माना गया है, उनमें भारत का नंबर 84 पर है। महाभ्रष्ट देशों की सूची में भारत आ गया है, जो कभी विश्व गुरु कहा जाता था, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उसको महाभ्रष्ट कहा है। उसके लिए सरकार serious नहीं है। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। बेनामी Transaction Prohibition Act 1988 में बना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। काले धन का उपयोग सबसे अधिक इसी में हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

सीबीआई न्यायालयों में 9,310 मामले पड़े हैं, दो हजार मामले दस साल पुराने हैं, 154 अनुमति के लिए सालों से पड़े हैं। अनुमति नहीं देते हैं। जो अनुमति नहीं देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराध को छिपाना भी एक अपराध है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। Corrupt Public Servant Forfeiture of Property Bill 1999 बिल पास करने की सिफारिश Law Commission न की थी। इसको पास कराइए। मुख्यन्यायाधीश कह चुके हैं कि इसको पास कराइए। सरकार गंभीर नहीं है, आज तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हैरानी की बात है कि लोकपाल बनाने का बिल Administrative Reform Commission की सिफारिश पर 1968 में सबसे पहले लोक सभा में लाया गया। चालीस साल हो गए, लेकिन वह लटका पड़ा है। सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है। लोकपाल बिल चालीस साल से लटका हुआ है।

मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब चाहूंगा, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एक affidavit दिया है, दिया कि नहीं दिया, क्या तथ्य है, मैं जानना चाहूंगा? मेरी जानकारी के मुताबिक उसमें कहा है कि जर्मनी सरकार ने सूचना दी है कि लिक्टेंस्टाइन बैंक में भारत के लोगों के गुप्त खाते हैं। Affidavit में

भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, लेकिन आखिर में कहा है कि उन्होंने शर्त लगाई थी कि आप इस सूचना को सार्वजनिक नहीं करें। अगर यह affidavit दिया है, तो आपने शर्त क्यों मानी? बेईमानों का नाम छिपाने की शर्त क्यों मानी? अगर आप ईमानदार हैं, तो बेईमानों के नाम छिपाने की शर्त क्यों मानी और नाम न बताने की बात कही है, कार्रवाई करने की बात तो नहीं कही। मैं जानना चाहूंगा कि उसमें असलियत क्या है? एक विचित्र बात, मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार बहुत गंभीर कैंसर के रूप में देश में फैल रहा है और इसके लिए पूरी दुनिया चिंतित है। मुझे इस बात की खुशी है कि भारत ही चिंतित नहीं है, बल्कि United Nations भी चिंतित है। United Nations Convention Against Corruption 2003 में बनी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट ने चिंता प्रकट की और एक convention बनाई।

मैं इसके लिए United Nations को बधाई दूंगा और इसकी भूमिका की चार पंक्तियां, जो UN Secretary-General, Mr. Kofi A. Annan ने लिखी हैं, उनको पढ़ना चाहूंगा—

> "Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organised crime, terrorism and other threats to human society to flourish".

और उसके अंत में कहा है कि यह जो convention है,

> "It makes a major breakthrough by requiring Member States to return assets obtained through corruption to the country from which they were stolen".

इसका उद्देश्य यह है कि अगर एक देश से करप्शन के द्वारा सम्पत्ति दूसरे देश में जमा की गई है, तो उस देश को वह सम्पत्ति लौटानी होगी। लेकिन हैरानी की बात है और मैं सरकार की तरफ से उत्तर चाहूंगा कि 2003 में इस convention को स्वीकृत किया गया। 140 देशों ने हस्ताक्षर किए और 120 देशों ने उसको ratify कर दिया, लेकिन भारत ने आज तक उसको ratify नहीं किया। आपने क्यों ratify नहीं किया? अगर दुनिया के 120 देश हस्ताक्षर करने के बाद इस convention को ratify कर सकते हैं, तो आपने उसको ratify क्यों नहीं किया? योंकि यह आम बात है और इस बात के बहुत से प्रमाण आ चुके हैं कि लगभग 60-65 लाख करोड़ रुपया केवल स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा है। यह पैसा इस देश का है, गरीबों का है, जो 28 करोड़ लोग झोंपड़ियों में कराह रहे हैं, उनका पैसा है। लोगों ने यह पैसा बेईमानी से लिया और विदेशों में जमा कराया और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने एक convention, एक तरीका अपनाया और महोदय, यह देखकर हैरानी हुई कि स्विट्ज़रलैंड ने इस पर sign भी कर दिए और स्विट्ज़रलैंड ने ratify भी कर दिया ! उसे नहीं करना चाहिए था। उसकी तो मौज हो रही है, दुनिया भर के बेईमान लोगों के पैसे पर वह देश मौज कर रहा है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने signature भी कर दिए, ratify भी कर दिया और भारत सरकार ने 2005 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आज तक इस convention को ratify नहीं किया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब हम चाहते हैं। अगर दुनिया के 120 देश यह कर सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं कर सकता?

महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि करप्शन के कारण गरीबी बढ़ती है, गरीबी के कारण विषमता बढ़ती है और गरीबी व विषमता आज इस देश में अपराध, तनाव और नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मैं अंत में इतनी ही बात कहना चाहूंगा.. मैं एक मिनट में खत्म करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार इन सारी बातों के बारे में गंभीर नहीं है। आपने पुराने संकल्प का ज़िक्र किया, इस देश में तो यह संकल्प पहले से ही है। मुझे याद है स्वामी विवेकानन्द ने सबसे पहले यह कहा था कि हिंदुस्तान के लोगो, इस देश के गांव का गरीब आपका देवता है। भूल जाओ, सभी देवी देवताओं को। जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं करता, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के गरीब आदमी की सेवा करो और उसे

उन्होंने "दरिद्रनारायण" कहा। फिर महात्मा गांधी ने अंत्योदय की बात कही और 63 साल पहले आपने यह संकल्प दोहराया, लेकिन आज देश की हालत क्या है? भ्रष्टाचार से देश टूट रहा है। गरीबी बढ़ रही है, महंगाई की मार से देश की हालत खराब है। आज इस सदन में उड़ीसा की बात कही गई। रोज़ खबरें आती हैं कि किस ढंग से भुखमरी से लोग मर रहे हैं। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि देश की सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करे। गरीबी और अमीरी रहेगी, भगवान भी उनको बराबर नहीं कर सकता, लेकिन अति गरीबी दूर होनी चाहिए। ...**(समय की घंटी)**... मैं दो मिनट में खत्म करता हूं। बुनियादी समस्याएं और दो वक्त की सूखी रोटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। शायद इसी बात को देखकर महात्मा गांधी जी ने अंत्योदय की बात कही थी।

जो अंत में है, जो सबसे गरीब है, उसका विचार सबसे ज्यादा करिए, लेकिन आज सरकार की नीतियां अन्त्योदय के आधार पर नहीं चल रही हैं। ये pro rich नीतियां हैं, जिससे गरीबी और बढ़ रही है और गरीबी बढ़ने के कारण देश में तनाव बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद बढ़ रहा है। यह जो नक्सल गलियारा है, यह गरीब गलियारा है। जहां-जहां गरीबी जितनी ज्यादा है, वहां-वहां नक्सलवाद उतना अधिक बढ़ रहा है। नक्सलवाद में दो प्रकार के लोग हैं - एक नेता हैं, जो उस मूवमेंट को चलाने वाले हैं, वे विचारधारा से प्रेरित हैं, लोकतंत्र में उनका भरोसा नहीं है, वे देश को तोड़ना चाहते हैं, बंदूक के सहारे काम करना चाहते हैं। नक्सलवाद का नेतृत्व करने वाले लोग अलग हैं, उनके साथ किसी किस्म की कोई दया नहीं होनी चाहिए। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि नक्सलवाद को मिटाने के लिए सरकार बहुत बड़ा प्रयत्न कर रही है, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं आनी चाहिए। पूरा देश उसके लिए सरकार के साथ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, उनके पीछे जो गांव के गरीब लोग चल रहे हैं, वे सभी विचारधारा के कारण साथ नहीं हैं। उनको बरगलाया जा रहा है, उनको फुसलाया जा रहा है - गरीबी और बेरोजगारी के कारण - जो इस रिपोर्ट में कहा है। इसलिए जब तक सरकार उन कारणों को दूर करने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक यह तनाव, यह नक्सल और आतंक की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

मैं जहां सरकार को बधाई दूंगा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें कोई ढील नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो इस रिपोर्ट में कहा है कि नक्सलवाद की भूमि जो इस देश के अंदर तैयार हुई, उस गरीबी और अति गरीबी को दूर करने के लिए युद्धस्तर पर काम होना चाहिए। आज वह नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो एक साल के बाद आप कहते कि हम पांच करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आए, लेकिन आपको यह कहना पड़ा कि 4 करोड़ 40 लाख लोग और ज्यादा गरीब हो गए। नक्सलवाद को दूर करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है। देश की गरीबी और विषमता एक बहुत बड़ा संकट है इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार युद्ध स्तर पर अति गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नयी नीतियां बनाए और बेईमानी तथा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए विदेशी धन वापस लाने का प्रयत्न करे। इस कन्वेंशन पर सिग्नेचर करे। स्विटज़रलैंड से पैसा वापस लाने का जो वायदा किया था - कुछ नहीं हुआ। इसमें भी केवल चलते हुए उसका जिक्र है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार आज यह कानून बनाए कि गैर कानूनी तरीके से विदेशी बैंकों में पैसा जमा कराना अपराध है - आज भी कानून है - उसमें यह करे कि अपराध है और उस अपराध के लिए 20 साल की सख्त सजा तय कर दे। अगर कोई ढिलाई देनी है तो उसमें 6 महीने का समय दे और कह दे कि 6 महीने के अंदर जो लोग स्वयं अपने धन की घोषणा कर देंगे, उनको रियायत दे दी जाएगी, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। सरकार के पास उनके नाम हैं, जिनके खाते विदेशों में हैं। उनके खिलाफ थोड़ी सी कार्यवाही शुरू कर दी जाए और 20 साल की सख्त कैद की घोषणा की जाए तो सरकार के दरवाजे पर उन सब बेईमान लोगों की लाइन लग जाएगी जिन्होंने देश का 60 लाख करोड़ रुपया लूटकर विदेशों में जमा कराया। हमने इतिहास पढ़ा है कि दुनिया के लुटेरे आए और हमें लूटा। इस बार तो हमें अपनों ने लूटा और उन

अपनों की कहीं आप रक्षा तो नहीं कर रहे, कहीं आप उनको बचा तो नहीं रहे? इस पर आज तक क्यों सिग्नेचर नहीं किए? जर्मन सरकार ने जो आपको नाम दिए हैं - एफिडेविट में आपने कहा है - उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बुनियादी समस्याएं हैं। कितने करोड़ किस काम पर लगाए - रूटीन के काम कोई भी सरकार करती - लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो बुनियादी सवाल था, जो संकल्प था, जिस संकल्प को आपने दोहराया था, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। गरीब त्रस्त है, गरीब निराश है, विषमता बढ़ रही है, भ्रष्टाचार कैंसर की तरह देश को खोखला कर रहा है।

भ्रष्टाचार चिंता का विषय है, सबसे चिंता का विषय यह है कि भ्रष्टाचार से सरकार ने समझौता कर लिया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है, यह और भी चिंता का विषय है। अंत में, मैं देश के उन करोड़ों लोगों को ध्यान में रखकर एक बात कहना चाहता हूं, वे दुखी हैं, निराश हैं, परे शान हैं। इस देश के गरीब लोगों ने बहुत बर्दाश्त किया है और झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी जब अपनी आंखों के सामने अपने भूखे बच्चों को देखता है और फिर देखता है कि कुछ लोग रातों-रात अमीर हो जाते हैं, उसके दिल पर क्या बीतती होगी? हम उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वह कब तक इंतजार करेगा? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी और देश के उन गरीबों को ध्यान में रखकर, मैं अपनी बात हिन्दी के एक कवि की चार पंक्तियों से समाप्त कर रहा हूं। इन्हीं लोगों की इस अवस्था का जिक्र करते हुए हिन्दी के कवि नीरज ने कहा हैं:—

"तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है,
बाग के बाग को बीमार बना देती है,
भूखे पेटों को देश-भक्ति सिखाने वालो,
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है।"

आप अधिक इंतजार मत करवाइये। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Rajniti Prasad, you take five minutes.

SHRI RAJNITI PRASAD (Bihar): Sir, I have seven minutes' time.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Let me make it clear...*(Interruptions)*... I want to make it clear. Otherwise, I will have problem. Among the 'Others' category, there are 13 names, and I have to divide the time equally. So, you finish in five minutes.

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मेरा सात मिनट बोलने का समय है, लेकिन मैं सात मिनट से पहले खत्म करूंगा।

सर, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। इस अभिभाषण में पैरा 74 है और पैरा 74 की सेकेंड लाइन से मैं शुरू करता हूं। यह जवाहर लाल नेहरू जी का कहना है कि भारत की सेवा का अर्थ है, उन करोड़ लोगों की सेवा, जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता, रोग, अवसर की समानता को समाप्त करना। सर, मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। डा0 राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, कर्पूरी ठाकुर वगैरह इस देश में राज का संचालन करते थे, तो हम लोग नारा लगाते थे कि इस देश में टाटा-बिरला की सरकार नहीं चलेगी। लेकिन अब टाटा-बिरला की सरकार का कोई मतलब नहीं है, अब टाटा-बिरला की सरकार गई। अब हम लोग...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You kindly address the Chair. They are trying to distract your attention...*(Interruptions)*... They are not supporting you. You kindly address the Chair.

श्री राजनीति प्रसाद : आप मुझे बोलने दीजिए। आपने भी हाथ जोड़ा था, मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं। मुझे आपका भाषण बहुत अच्छा लगा था। सर, पहले मैंने कहा था कि जब मैं बचपन में समाजवादी आंदोलन से जुड़ा था, तो मैंने समाजवादी नारा लगाया था कि इस देश में पूंजीपतियों का राज नहीं चलेगा। सर, मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 को जो भाषण दिया, उसी संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि आज नये प्रयोग किए गए हैं। अब टाटा-बिरला की कोई बात नहीं है, अब यहां पर कॉरपोरेट बॉडी आ गई है। कॉरपोरेट बॉडी और वायदा बाजार इसलिए आया कि किसानों को कुछ राहत मिलेगी, जो पैदावार करने वाले हैं, उनको राहत मिलेगी, जो आदमी कच्चा माल पैदा करता है, उसको राहत मिलेगी। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको राहत नहीं मिली, किसानों को राहत नहीं मिली, बल्कि वायदा बाजार और कॉरपोरेट बॉडी को कई हजार करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

यह देश वायदा बाजार और कॉरपोरेट बाडी से चल रहा है, इसीलिए इस देश में महंगाई है। सर, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि हमने यह कहा था कि आपने एक *नरेगा* नाम से योजना चलाई है और उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया है। हमने कहा कि *नरेगा* अकार्थ हो गया, *मरेगा,* तो हमने कहा कि *मरेगा* नहीं, इन लोगों ने कहा कि भई, बहुत झांझाट करते हैं, *मरेगा* नहीं है। सर, अगर महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया और आप शॉर्ट फार्म में *नरेगा* कह रहे हैं, तो हम उसको *मरेगा* क्यों नहीं कहें। हमने यह कहा था कि आप महात्मा गांधी का नाम बदनाम मत करिए, क्योंकि *नरेगा* पवित्र चीज है। आपने यह अच्छा काम किया है, लेकिन सर, किस राज्य में क्या है, हम इसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टचार, सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं है, तो आपने जो *नरेगा* में 40 हजार करोड़ दिया है, उसमें है। इससे किसी को कोई रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि रोजगार कार्ड मिलता है। इसमें सब बिचौलिया और दलाल लोग शामिल हैं। मैंने जो *नरेगा* के लिए *मरेगा* कहा था, वह सही है। इस *नरेगा* में पर्याप्त भ्रष्टाचार है, इसलिए इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए। सर, नुरूल हसन जी यहां पर शिक्षा के कैबिनेट मिनिस्टर थे और बड़े ही विद्वान आदमी थे, अभी नहीं हैं। वे पश्चिमी बंगाल में गवर्नर भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पांच वर्ष तक बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण तथा अच्छा खाना नहीं दिया तो इसकी वजह से जो उसमें कमी आएगी, वह बाद के दिनों में ठीक नहीं हो सकती है। सर, आपने सर्वशिक्षा अभियान चलाया है। आप गांवों में जाकर देखिए, हो सकता है कि एक-दो राज्य में इस पर अच्छा काम हो रहा हो, मैं अंडेमान निकोबार गया था, तो मैंने वहां पर देखा सर्वशिक्षा अभियान ठीक चल रहा है। अधिकतर जो राज्य हैं, आप उनमें जाकर देखें कि वहां पर स्कूल तो हैं, बिल्डिंग हैं और कहीं-कहीं पर तो बिल्डिंग भी नहीं है और बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। वहां पर बच्चों को मिड-डे-मील दिया जाता है। मैंने एक जगह पर वहां के मास्टरों से कहा कि यह मिड-डे-मील आपको खाना पड़ेगा। हम लोग एक जगह चेकिंग पर गए थे और मास्टरों से कहा कि आप लोग यह मिड-डे-मील खाइए। उन्होंने कहा कि हम यह नहीं खाएंगे, क्योंकि मिड-डे-मील से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अभी शांता कुमार जी ने भी कहा है कि इसमें काफी भ्रष्टाचार है और गरीबों को मिलने वाले अनाज में भी भ्रष्टाचार है। हमें इस भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मिड-डे-मील ...**(समय की घंटी)**... अभी

पांच मिनट तो हुए नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आपके 6 मिनट हो गए हैं।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें डिफ्रेंस आया है। मैं उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**... आप ऐसा मत करिए। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उन परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने हाल के पुणे में आतंकवादी हमले में अपने प्रियजन खो दिए। सर, यह अकेले पुणे की घटना नहीं है। इससे पहले मुम्बई में आतंकवादी हमला हुआ है और शायद इसके बाद भी ऐसा हमला होने वाला है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): ऐसा मत बोलिए।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, अभी और जगहों पर भी होने वाला है, ऐसा मैं कहने वाला हूं- यह सांसद भी तो गवाह है। ...**(समय की घंटी)**... मैं आप से यह कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार): सर, ये फेयरवेल लिस्ट में हैं, इनको बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): नहीं, नहीं। यह आपका टाइम नहीं है और यह आपकी पार्टी का टाइम भी नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री राजनीति प्रसाद: सर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा के मामले के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। यह गंभीर सवाल है अगर आप इस पर विचार नहीं करेंगे, तो ये घटनाएं और घटती रहेंगी। जो हमारा खुफिया तंत्र है, उसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं खड़ा होता हूं, तो सभी लोग पीछे ही पड़ जाते हैं। मुझे पता नहीं है कि क्यों पीछे पड़ते हैं, समझा में नहीं आता। सर, ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Shantaram Laxman Naik. Please note that you have 20 minutes. You just adjust your speech accordingly.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand here to support the Motion moved by you and seconded by Shri Santosh Bagrodiaji. On that account, I should get five minutes more. Sir, the Presidential Address is not a ritual, it is an event. I say it is an event because even during my college days, I used to see the next day's newspapers front pages were full of the Address of the President. Today, Sir, I see that the President of India's Address is put by several newspapers in inside pages. Only if there is some rape item or murder cases or film star marriages, film stars divorces are not there then only the Presidential Address gets front page. This is the scenario. I speak with all seriousness. Kindly use your good offices with media that our President of India's Address must be treated as an event and it should get its due respect in media too. Sir, अभी शांता कुमार जी ने ऐसा कहा कि इन पचास-साठ सालों में कुछ नहीं हुआ है। लाखों रुपए खर्च कर दिए, लोग गरीब रहे, कुछ नहीं हुआ, देश जैसा था, वैसे का वैसा रहा, उन्होंने इस तरह की पिक्चर दी है।

First of all, I would like to know as an Opposition Party what was your role and as a ruling party in various States that you are ruling what you are doing. In some States, there is practically State terrorism, it has been proved. आप लोगों से पूछिए, पीछे भागकर छुरी, चक्कू से मारने लगे। आपने उन लोगों को encourage किया, आपने इस तरह के राज चलाये हैं।

We must have, perhaps, failed in giving food to some people, shelter to some people. ...*(Interruptions)*... What did you do in those States where you are ruling? Please consider this.

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): दिल्ली में 84 के दंगे पहले हुए...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : मिस्टर पाणि, आप बैठिए...(व्यवधान)...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: It appears that you have no appreciation; the Opposition has no appreciation for the way we withstood our recession. ...*(Interruptions)*... They have no appreciation for the way we withstood recession. You do not give any cooperation

for running of the House. You appear to be jealous of the progress that the country has made under the leadership of the Congress Party. You are very, very jealous that is why you are playing a role of destructive opposition rather than playing the role of a constructive opposition.

SHRI BIRENDRA BAISHYA (Assam): This is not true. ...*(Interruptions)*... You cannot blame everybody.

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: You are in minority in Lok Sabha. ...*(Interruptions)*... Your allies are not supporting you on the issue of price rise in the Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please address the Chair. ...*(Interruptions)*... Mr. Pany, please. Do not get provoked by what he says. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, the President of their party...*(Interruptions)*... I am submitting that the President of their party does not even know the Constitution of the country. He has come on deputation from RSS to their party. He is telling that for price rise the Congress President has to reply. This is what your President is saying. Please show him the Constitution of India, please tell him how we govern. Your President who has been recently appointed against your wishes ...*(Interruptions)*... Okay, elected. He is telling that

SHRI RUDRA NARAYAN PANY: Our president is not born, he is elected. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Shantaram, you focus on the Motion.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: I am focusing on the Presidential Address. We don't have to learn lessons from such people.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You speak on the Presidential Address.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, we are a coalition Government and in this respect I think, we have to think of having some sort of constitutional amendment for running a coalition Government. I am saying in a broad aspect because coalition Governments are going to be there for some time at least. Therefore, there must be a provision in the Constitution, there must be an independent chapter because certain eventualities come and therefore, there is a need that the provisions in the Constitution should be there to regulate the functioning of a coalition Government.

Now, Sir, as a Parliament we are giving relief to everybody. But, there is a need today to restore our own powers. We say that Parliament is supreme. But, unfortunately, it is not supreme in my submission. Today, most of our powers have been taken away by the Supreme Court. Partly they have been taken away by the Election Commission and hardly have they got any power left for our functioning. The other day there was a decision of the Supreme Court.

There is a Central Act under Section 6 of Delhi Police Establishment Act which says that instead of CBI, State permission is required. It is very clearly written. There is no ambiguity. There is no scope for a different interpretation and Supreme Court says, 'we are a constitutional court and if we require we can order anybody to investigate. We can ask CBI to investigate in any case'. This is the sort of interpretation that they are doing. Tomorrow, as a Member of Parliament anyone of us can make a submission and as Supreme Court will say, it violates article 21 of the Constitution and therefore, we can haul you up and when an occasion arises you say 'okay, we have got privileges. Nobody can question us.' No, they will say, 'your privileges are not even codified. At least Section 6 is codified and they have interpreted differently. Privileges are not codified and therefore, each one of us can be hauled up under article 21 if this interpretation which Supreme Court is now coming forward is taken into consideration. Let us consider this aspect.

Secondly, Sir, we are doing a lot of development in various fields. Various State Governments are also doing, but, one problem arises in the course of development. The problem is, there is regional imbalance irrespective of political parties. Supposing there is a Minister with a particular portfolio. He will concentrate and give finances only to his constituency, whether he is in the ruling party or otherwise. Therefore, constitution should provide for balanced development compulsorily. Supposing 'X' amount is available, that amount is distributed properly in all regions. At present, there are no provisions in the Constitution and if a Minister wants, then, he can practically give 90 per cent in one constituency. There is no scope for others. So, therefore, this is a serous problem faced by many State Governments and perhaps in Central Government also. I won't name the Ministry but a question arises that we should look into this aspect so as to have a balanced growth.

Then, Sir, President of India has also spoken about natural calamities. Now, Sir, earthquakes takes place in various parts of the world. We are also not immune from that. In the first year, droughts are there and therefore, a machinery of disaster management is required to be tightened and we should have disaster management institution throughout the country. We have hardly got three or four institutions and they are also not functioning. If these institutions are there, the personnel will be trained properly to assess the damage, to assist people technically and in a professional manner. Therefore, this is required. Today, we are in an era of e-governance. If e-governance has to be successful then, websites of Governments — whether it is Central Government or State Governments — have to be perfect. In many States, websites are not updated. The gadgets of the Government are not put on-line. I doubt whether the Government of India's Gazette is available on-line immediately.

I think, it is not available most of the time. I am very proud to say that my State put on website immediately. Recently, a Gazette was published on Thursday and we have put it on website on the very same day evening. All notifications, orders and everything that the

Government passes will put on website immediately. So, every State Government should have these on-line.

Sir, the Right to Information has given the responsibility to departments to put all information on website. There is a clear-cut provision. Nobody respects the provision. Therefore, the RTI should be amended to haul up or to make the departmental head responsible if information pertaining to a particular department is not put on website. The RTI is a very good legislation. Somehow, the right to information is coming in our way. I am not saying our way. Sir, if I ask a question through the RTI, I get a better reply than I get, through you, from Parliament. Sir, three or four questions are clubbed and replies are not practically given, whereas under the RTI you get full answer. Whom you haul up here? You cannot question the Ministers. There is no punishment provided. But, punishment is provided under the RTI. Therefore, kindly look into this aspect also.

Sir, tourism is important not only for Goa but also for the country. We require a healthy tourism. The recent developments in Goa are worth mentioning here. Foreigners come to Goa and are mostly Russians. Sir, about 40,000-45,000 Russians come to Goa every year. They come on Tourist Visa and do business by violating the FEMA. They come, give money to some brokers, buy a food joint, sit on cash-counter and run business. If he is questioned, he will say, 'I am the Manager of this hotel.' The entire business is done by these people by violating the FEMA. Not only that, I am giving another example. There is a system of motorcycle taxi in Goa. Many hon. Members must have gone to Goa and found that poor people operating these motorcycle taxis or doing this business. One passenger sits as pillion rider and pays money for taking him to his desired destination to the motorcycle taxi driver. Now, Sir, Russians are driving motorcycle taxis in Goa! And, our poor local people are just watching helplessly. The local motorcycle owners prefer to give motorcycles to Russians as they, obviously, pay more. So, locals do not get motorcycles. And, in villages, they move in a scanty dress. And, on beaches, in remote areas, they move without any clothes. This is the scenario. In villages, they move with scanty dress. All school children pass by and see them. So, this is the situation there. They incite locals and pick up quarrels. Drugs is a regular business. There are certain mafia elements. I don't say that all of them are like that; there are some genuine cases also. Mafia and other elements do this drug business. Therefore, what I suggest is that the FEMA regulations have to be tightened. Those who do business unauthorisedly and violate the FEMA should be hauled up. The State Government has also the responsibility to perform in this.

Sir, in the President's Address, she said that we have zero tolerance as far as terrorism is concerned. But, at the same time, the machinery which will counter with terrorism has to be tightened. Our prosecution machinery in States is not updated. They don't have modern gadgets and modern amenities. In Goa, I had gone to the Prosecution Directorate and found that none of the Public Prosecutor has any computer. I offered laptops under the MPLADS to all

the Assistant Prosecutors. But, this has to be done on a bigger scale so that they do not suffer in the matter of prosecution.

Then, Sir, as far as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is concerned, it is going on well. Possibly, there may be corruption, as you have stated. But the State Governments will take action. I would like to suggest one amendment in that. Today, it caters to the job-related needs of the lower strata of the society, that is, the labour class. But in many parts of the country, there are middle class people who cannot go to fields, who cannot do a labourer's job. They are also very poor people. In many such families there is nobody to earn. I would suggest if a boy or a girl from such families could get some sort of employment, under this scheme, which is clerical in nature, it would go a long way to help them. A very poor man to go to the fields and work as a labourer, but for these poor lower-middle-class people their prestige in the society comes in their way. So, an amendment should be brought forward in this respect.

Now, I come to micro financing. I very much appreciate that a lot of money has been given to finance the Self-Help Groups. The evolution of Self-Help Groups is a revolution in the country. But since more and more money would be coming in their hands, I have been saying, time and again, that Self-Help Groups have to be registered under the Societies Registration Act so that when finances go to them, they could be held responsible. If the Societies Registration Act is strict, then, a simple law can be enacted, but they must be registered.

So far as the National Highways are concerned, numbering of National Highways is going to be done. Their numbers have also been given on the department's website. In this regard, I would like to make a humble submission to the hon. Minister that two National Highways, out of these, should not be numbered — one, which is going from Srinagar to Kanyakumari, and the other one which is going from Porbandar to Silcher. These two National Highways should be named as the Mahatma Gandhi National Highway-1 and the Mahatma Gandhi National Highway-2 in order to unite the entire country from North to South and East to West. To symbolise this spirit, I would suggest that these two National Highways should be named after the name of Mahatma Gandhi and rest of them can be numbered.

Of late, another phenomenon has been noticed. We see on television that there are *sadhus* and *dhongi babas* throughout the country, who are indulged in rapes, murders and extortion. They extort money from the people befooling them that if they give them money in such and such *muhurat*, it will multiply four times, but if they would give money the next day, that would multiply only into double. In this manner, they loot people. *(Time-Bell)* Therefore, I would like to suggest that a country-wide survey should be conducted by the Government of India and should find out the *sadhus* who are involved in such acts. Such *sadhus* should be prosecuted in the strictest manner.

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप दस मिनट में खत्म करेंगे?

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): जी सर।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, try if you can.

श्री वीर सिंह: मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दिशाहीन है, आम आदमी की उपेक्षा करने वाला है तथा आंकड़ों का पुलिन्दा है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आम आदमी को राहत देने की बात की है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान विकास दर 8 प्रतिशत किए जाने की बात भी आंकड़ेबाजी के सिवाय कुछ नहीं है।

सच्चाई यह है कि UPA सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और आंकड़ों की जादूगरी के बल पर वह देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है।

मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश से गरीबी दूर करने के लिए किसानों तथा आम आदमी के विकास की बात कही है। मान्यवर, देश को आजाद हुए 62 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इस देश में गरीब, गरीब होता चला गया, अमीर, अमीर होता चला गया। किसानों की बात कही गई है, इस देश में 70 प्रतिशत लोग खेती से जुड़े हैं, किन्तु केन्द्र सरकार की तरफ से उन किसानों के प्रति कोई अच्छी पहल नहीं की गई है। आज देश में किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है — समय पर उसको खाद नहीं मिलती, उसको उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। जब खेत से अनाज कटता है तो उसकी फसल का दाम बहुत सस्ता होता है, लेकिन जब वह अनाज किसान के घर से चला जाता है तो उसका दाम दस गुना बढ़ जाता है और किसान हाथ मलता रह जाता है। उसको उसकी मेहनत का और उसने अपनी खेती में जो लागत लगाई होती है, वह लागत भी नहीं मिलती है। इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि उसे किसानों के बारे में सोचना चाहिए। कभी नारा दिया गया था - जय जवान जय किसान, सीमा पर जवान, खेत में किसान। किसान अन्नदाता होता है, सबको अनाज पैदा करके देता है और यदि किसान खुशहाल है तो पूरा देश खुशहाल है, क्योंकि देश की तरक्की किसान से जुड़ी है। यदि किसान के पास अच्छी फसल होगी, पैदावार अच्छी होगी, उसकी आमदनी अच्छी होगी तो उससे मजदूर भी सुखी होगा और व्यापारी भी खुशहाल होगा। क्यों होगा? क्योंकि, जब किसान के पास पैसा आएगा तो वह मकान बनाएगा, मकान बनाएगा तो सरिया खरीदकर, सीमेंट खरीदकर और मकान में लगने वाली सब वस्तुएं खरीदकर लाएगा। कहां से खरीदकर लाएगा? व्यापारी से खरीदकर लाएगा। शादी करेगा, अच्छी शादी करेगा, जेवर अच्छे बनाएगा। कहां से लाएगा? व्यापारी से लाएगा और इसलिए किसान यदि खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, किन्तु किसानों की तरफ नहीं देखा जाता।

आज किसान आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? मजबूर होकर कर रहा है। क्योंकि, किसानों को, जो मध्यम किसान हैं, सरकार ने उनको ऋण देने की कोई सही व्यवस्था नहीं की है। आज किसान, मध्यम किसान सेठसाहूकारों से ज्यादा ब्याज पर पैसा लेता है। जब पैसा नहीं बचता है, फसल सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है तो विवश होकर आत्महत्या करता है। इन सबके रहते किसान आज महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहा है और दुख की बात यह है कि वहीं से हमारे देश के कृषि मंत्री, श्री शरद पवार जी हैं। वे पूरे देश के किसानों के बारे में क्या सोचेंगे, वे अपने महाराष्ट्र के किसानों के बारे में ही सोच लें। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वहां का किसान आत्महत्या करने पर विवश है। आज महाराष्ट्र में कोआपरेटिव की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि वहां पर किसानों का गन्ना खेत में ही सूख जाता है। मैं महाराष्ट्र में घूम रहा था, मैंने अपने साथियों से पूछा कि यह गन्ना खेत में क्यों खड़ा रह गया है, मिल में क्यों नहीं गया है, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि यहां पर कोआपरेटिव्स का कब्जा है और कोआपरेटिव्स शरद पवार जी के हाथ में है।

यहां पर पंचायत के चुनाव में जिसने मिल-मालिक के कहने पर सरपंच को चुनने के लिए वोट नहीं दिया, उस मिल-मालिक ने उस किसान का गन्ना नहीं खरीदा, इसलिए गन्ना सूख रहा है। खेतों में किसान का गन्ना सूख रहा है, जाकर देख लो, सर्वेक्षण कर लो, अभी भी गन्ना खेतों में सूख रहा होगा। ऐसी व्यवस्था है महाराष्ट्र के अंदर और आज महाराष्ट्र के 7-8 जिलों में पानी की भी समस्या है।

जो विदर्भ है या मराठवाड़ा है, जिधर पानी नहीं है, पानी गहराई में है, वहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ-साथ जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड है, वहां पर भी जमीन के अंदर पानी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने केन्द्र सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी कि किसानों के हित के लिए, वहां के गरीब लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए उत्तर प्रदेश को 80 हजार करोड़ रुपए का पैकेज मिलना चाहिए। उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी, किन्तु केन्द्र सरकार ने आज तक उनकी बात नहीं सुनी। केन्द्र की सरकार, UPA की सरकार, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही है, वह एक ओर गरीबों की बात करती है और जब गरीबों की बात कही जाती है, तो उनकी अनदेखी की जाती है, यह सौतेला व्यवहार क्यों? उत्तर प्रदेश, देश का पांचवां हिस्सा है, सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोग वहां रहते हैं, 100 करोड़ की आबादी में से 20 करोड़ लोग अकेले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो आबादी के हिसाब से केन्द्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को पैकेज क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह सौतेला व्यवहार नहीं है, तो क्या है? इसलिए आपको किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनको जरूरी साधन मुहैया कराने चाहिए। यदि किसान खुशहाल होगा, तो देश खुशहाल होगा और गरीबी दूर होगी। जब गरीबी दूर होगी, तो उग्रवाद भी दूर होगा, नक्सलवाद भी दूर होगा और और लड़ने की भी क्षमता होगी।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: गरीबी से उग्रवाद का क्या ताल्लुक है?

श्री वीर सिंह: गरीबी का ताल्लुक बेरोज़गारी से है। जब बेरोज़गारी दूर होगी, तो गरीबी भी दूर होगी और गरीबी दूर होगी, तो आदमी गलत काम करने के लिए विवश नहीं होगा, इसलिए इसका ताल्लुक है। जब देश में आम चुनाव हुआ था, जो कांग्रेस ने एक नारा दिया था – "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ", किंतु इसका उलटा हुआ। जो नारा दिया था - "कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ," अब वह नारा हो गया - "कांग्रेस का हाथ पूंजीपतियों के साथ"। कैसे? ...**(व्यवधान)**... कृपया आप लोग मेरी बात सुन लें, मैंने आप सबकी बात सुनी, मैं बीच में नहीं बोला, आप लोगों में सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आप लोगों को सच्चाई कड़वी क्यों लग रही है?

उपसभाध्यक्ष जी, यह नारा क्यों उलटा हुआ, यह मैं आपको बता रहा हूं। जब इन्होंने नारा दिया था, जब लोक सभा के आम चुनाव हुए थे, उस समय यह नारा दिया गया था, यह नारा देकर इन्होंने वोट लिए, ये सत्ता में आए। जब UPA की सरकार थी, तो डीज़ल के दाम तीन बार थोड़ा-थोड़ा करके कम किए। जैसे ही फिर सरकार बनी, तो बिना बजट का इंतजार किए, इसी UPA सरकार ने पहले सत्ता में आने पर जो डीज़ल और पेट्रोल का दाम तीन-चार बार में कम किया था, उसे एक ही झटके में तीन-चार बार से ज्यादा बढ़ा दिया है, क्यों बढ़ा दिया, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ा दिया, क्योंकि जब डीज़ल की कीमतें बढ़ीं, तो भाड़ा बढ़ा, भाड़ा बढ़ा, तो महंगाई बढ़ी और इसकी मार सीधे गरीब पर पड़ी। एक तरफ UPA की सरकार किसानों के हित की बात करती है, गरीबों के हित की बात करती है और दूसरी तरफ गरीबों के हित पर कुठाराघात करती है। यही नहीं, पिछली बार जब भारत अमरीका के परमाणु करार को लेकर संसद में अविश्वास मत आया था, तो माननीय राहुल गांधी जी ने कलावती का नाम लिया था कि मैं महाराष्ट्र में गया था, यवतमाल गया था, यवतमाल में मैं कलावती के घर गया था और उन्होंने कहा कि "Kalawati is very poor."

बोला, ताली क्यों नहीं बज रही है, ताली बजवाइए। कलावती का घर टूटा-फूटा है, कलावती के बच्चों के खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, कलावती के घर में करंट नहीं है।* इस देश के अंदर एक

*Expunged as ordered by the Chair.

कलावती नहीं है, करोड़ों कलावती जैसी महिलाएं हैं, जिनके पास कपड़ा नहीं है ...**(व्यवधान)**... मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बोला गया है ...**(व्यवधान)**... मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, listen to me, Mr. Veer Singh. You cannot take the name of an hon. Member of the other House. That name may be removed from the proceedings.

श्री वीर सिंह: मान्यवर, इस देश में एक कलावती नहीं, ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, जिनके घर में करंट नहीं है। इस देश के अंदर करोड़ों लोगों की कलावती जैसी दयनीय हालत किसने की है? यह कांग्रेस ने की है। मैं सिद्धांत के आधार पर कह रहा हूँ। देश को आजाद हुए 62 साल हो गए। इन 62 साल के प्रजातंत्र काल में 50 साल शासन कांग्रेस का रहा है, तो यह देन किसकी है? अब यह नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। क्या गरीब के घर में जाने से पूरे देश के गरीब को खाना मिल जाएगा? क्या गरीब के घर में जाने से पूरे देश के गरीब का घर पक्का हो जाएगा?...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude. You have taken twelve minutes.

श्री वीर सिंह: मान्यवर, इसके साथ-साथ ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती जयन्ती नटराजन (तमिलनाडु): अब आप हाथी के बारे में कहिए ...**(व्यवधान)**...

श्री वीर सिंह: हाथी पूरे देश में, तमाम मंदिरों पर और तमाम जगह खड़ा हुआ है ...**(व्यवधान)**... पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ है ...**(व्यवधान)**... हाथी सब जगह है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please, conclude. कृपया आप समाप्त कीजिए।

डा. अखिलेश दास गुप्ता (उत्तर प्रदेश): आपको हाथी से क्या परेशानी है? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अखिलेश जी, आप कृपया बैठिए।

श्री वीर सिंह: यह पावर का हाथी है ...**(व्यवधान)**... आप हाथी से क्यों घबरा रही हैं? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude.

श्रीमती जयन्ती नटराजन: हाथी के बारे में स्पष्टीकरण ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. (Interruptions) No, no. Do not disturb. ...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंह: महोदय, बीच में व्यवधान आया है, मेरा पांच-सात मिनट व्यवधान में निकल गया है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): कृपया आप समाप्त कीजिए।

डा. अखिलेश दास गुप्ता: सर, व्यवधान आया है, पांच-दस मिनट तो उसमें चला गया...(व्यवधान)...

श्री वीर सिंह: मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" का भी जिक्र किया है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में माननीया मुख्य मंत्री जी ने ultra mega powerhouse लगाने की बात कही, जिसके लिए केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी **(समय की घंटी)** कि गरीब के घर में भी रोशनी जानी चाहिए, किन्तु अभी तक नहीं किया गया ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): ठीक है, हो गया; अब आप समाप्त कीजिए।

डा. अखिलेश दास गुप्ता: सर, अभी पार्टी का समय बाकी है ...**(व्यवधान)**...

श्री **वीर सिंह**: महोदय, अभी 17 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं ...**(व्यवधान)**... अभी हमारा समय बाकी है ...**(व्यवधान)**...

डा. अखिलेश दास गुप्ता: सर, अभी हमारे पार्टी का समय बाकी है ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is right. Since you have raised that point, let me explain. There is an understanding reached to reduce the time of every Party as the hon. Prime Minister would be replying at 4.30 P.M. Every Party's time, including the Congress Party's, has been reduced. I am only requesting you to keep that in mind and cooperate.

श्री वीर सिंह: महोदय, मैं दो मिनट में समाप्त करता हूँ। मान्यवर, सारे गरीब के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं आवास मुहैया कराने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई है...**(व्यवधान)**... जब कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से "मान्यवार कांसीराम शहरी गरीब **योजना**" तथा "सौजन्यहिताय शहरी गरीब मकान स्लम एरिया मालिकाना हक योजना" शुरू की है।

उसी प्रकार से इसके लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। रही बात सर्व शिक्षा अभियान और मिड-डे मील की, तो शिक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अंदर आज दोहरी शिक्षा प्रणाली है। गरीब का बच्चा प्राइमरी में पट्टी पर बैठकर पढ़ रहा है, जबकि अमीर का बच्चा convent में पढ़ रहा है, तो बराबरी कहां है? सर, समान शिक्षा होनी चाहिए। सरकार की यह नीयत होनी चाहिए कि गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। यदि आपकी नज़र गरीबों की तरफ है, तो गरीबों के बच्चों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए शिक्षा की तरफ भी आपका कदम उठना चाहिए। आज जो technical colleges हैं, उनमें जो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। आज पूरे देश के अंदर जो शिक्षण माफिया पैदा हो गए हैं, उन शिक्षण माफियाओं पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। आज गरीबों का हित नहीं हो रहा है। ...**(समय की घंटी)**... गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्योंकि उनको शिक्षित नहीं कराया जा रहा है। अब रहा मिड-डे मील का मामला ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं दो मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): नहीं, नहीं.... प्लीज़....**(व्यवधान)**... Your time is going to exhaust, only one minute is left. ...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंह: सर, बी.पी.एल. राशन कार्ड के बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude. ...*(Interruptions)*... There is only one minute more. I will not allow more than that. ...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंह: मान्यवर, बी.पी.एल. राशन कार्ड बहुत पहले बने थे, जो पात्रता के आधार पर नहीं बने। तब केंद्र सरकार ने पुनः सर्वेक्षण कराकर पात्रता के आधार पर बी.पी.एल. कार्ड बनवाए। ये कार्ड कौन बनाता है? देश के हर ज़िले में जब बी.पी.एल. राशन कार्ड बनते हैं, तो सरकारी कर्मचारी कहां जाता है? वह सरपंच या प्रधान के घर जाता है और हर गांव में दो-तीन पार्टियां होती हैं। हर गांव में ...**(समय की घंटी)**... सरपंच या प्रधान जिनके नाम बता देता है, उनके नाम बी.पी.एल. लिस्ट में आ जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंह: उससे पांच व्यक्ति लिस्ट में आ जाते हैं ...**(समय की घंटी)**... इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकर सर्वेक्षण कराकर ...**(समय की घंटी)**... ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Prof. Anil Kumar Sahani...*(Interruptions)*...

श्री वीर सिंह: इन व्यक्तियों के बी.पी.एल. कार्ड बनवाए, जिससे कि उनको फायदा मिल सके। मान्यवर, आपने मुझे पूरा समय ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): प्लीज़.... आप बैठिए....बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए।

श्री वीर सिंह: मान्यवर, हमारी पार्टी की जो मंशा थी ...**(व्यवधान)**... धन्यवाद।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान): सर, वीर सिंह जी बहुत अच्छा बोले, ज़ोर से बोले, वीरता से बोले, but he has used a word "आतंकवाद" कि आतंकवाद खत्म हो जाए, लेकिन आतंकवाद की अलग ही वजह है। अगर ये उसको उग्रवाद से replace कर दें तो अच्छा रहेगा।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): ठीक है। Now Prof. Sahani. Your time is 9 minutes. Please stick to that.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

प्रो. अनिल कुमार साहनी (बिहार): उपसभापति महोदय, आदरणीय सभी सदस्यगण, संसदीय जीवन की यह मेरी सबसे पहली स्पीच है। महोदय, राष्ट्रपति महोदय द्वारा 22 फरवरी को संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने के लिए मैं आज यहां खड़ा हुआ हूं। साथियों, आज देश में जो दोहरी नीति की बात चल रही है, वह सरासर सही है। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के साथ भेदभाव किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जहां इनकी सरकार नहीं है, वहां हर समय भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो या पश्चिमी बंगाल हो, हर जगह इनका इस प्रकार का काम चल रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहूंगा, जिनकी राष्ट्रपति महोदया द्वारा अपने अभिभाषण में कोई चर्चा नहीं की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, नस्लवाद चल रहा है, उनका राष्ट्रपति महोदया द्वारा कोई ज़िक्र नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में हमारे बिहार के जो लोग जाते हैं, वे मज़दूरी करने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां उद्योग नहीं हैं। हमारे मज़दूर वहां काम करने जाते हैं। आज महाराष्ट्र में किस प्रकार से हमारे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। वहां उत्तर पश्चिम के - उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के लोगों के साथ गुंडागर्दी की जाती है और उनको वहां से भगाया जाता है। वहां तो आपकी सरकार है, यू.पी.ए. की सरकार है।

इस यूपीए सरकार के अंतर्गत किस तरह से हमारे लोगों को जो वहां काम करने के लिए वहां जाते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। तो क्या यह क्षेत्रवाद और भाषावाद को बढ़ावा नहीं है? आपने किस प्रकार से कानून बनाया कि जो मराठी जानने वाले लोग हैं, उसी को महाराष्ट्र में कार चलाने की परमिशन दी जाएगी। उस कार चलाने वाले को, जो दूसरे प्रदेश का है, जो मराठी जानने वाला है, जो 15 वर्ष से वहां रहता है, उसी को ही कार चलाने की परमिशन दी जाएगी। महोदय, खासकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, असम से लोग वहां कमाने के लिए जाते हैं क्योंकि इन राज्यों में रोजगार नहीं है। हम लोगों के यहां रोजगार की व्यवस्था नहीं है। इन सब जिलों में, उत्तर पश्चिम में किसी प्रकार के उद्योग नहीं हैं। वहां पर जो उद्योग नहीं चल रहे हैं, उन उद्योगों को चलाने के लिए भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आपने किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। आज किसी भी राज्य में हजारों-सैकड़ों उद्योग खुले हुए हैं और किसी राज्य में एक-दो उद्योग भी नहीं है। इस उद्योग नीति में भी आपको समानता लाने पर विचार करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में समानता रहे। लोगों को अपने घरों में, अपने प्रदेश में रोजगार मिल सके और वे वहां पर काम कर सकें। महोदय, मछुआरों के संबंध में, फिशरमैन के संबंध में जो बात की गयी है, उनके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि समुद्र के तट पर जो मछुआरे रहते हैं, उन मछुआरों को तो काम मिल जाता है, लेकिन हमारे बिहार में जब सुखाड़ आता है, जल सूख जाता है तो जो लोग मछली पर निर्भर हैं, जो जल श्रमिक हैं, जो जल में काम करने

वाले लोग हैं, उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। आज वे लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। जब आपदा आती है, हमारे बिहार में आपदा आती है, सुखाड़ आ जाता है तो वहां का जल सूख जाता है और जल के सूख जाने के कारण जो लोग पानी पर आश्रित हैं, जो पानी में काम करने वाले जल मजदूर हैं, वे बेरोजगार हो जाते हैं और उनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पाता है। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपदाकाल में उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह सुरक्षा पेंशन के रूप में भी दी जा सकती है। उन गरीबों को और मछुआरों को राहत देनी चाहिए।

महोदय, यहां इस सदन पर आतंकवाद पर बहुत चर्चा हुई। आज नक्सलवाद पर, व्यवस्था परिवर्तन पर, सामंतवाद पर और सामंती विचारधारा पर भी बहुत सी बातें हुईं। यह किसकी देन है? आज महंगाई के कारण ये सब चीजें पनप रही हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था – "गरीबी हटाओ"... मगर आज कांग्रेस पार्टी के लोग, और कांग्रेस में जो लोग सत्ता में हैं, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से जो लोग गरीबी हटाने की बात करते थे, जो "गरीबी हटाओ" का इंदिरा गांधी का नारा था, आज उसकी जगह यह हो रहा है कि गरीब को मरवाओ, भूखा मरवाओ। आज हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों ने दाल खाना छोड़ दिया है, चीनी खाना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? आपकी महंगाई की नीति के कारण छोड़ दिया है। आपने जो महंगाई बढ़ाई है, उस महंगाई के कारण गरीब मर रहा है। आज हमारे यहां जो माड़ होता है, जो उसका सूप होता है, जो उसका पानी होता है, उसको दाल में नमक और तेल मिलाया जाता है और फिर वह रोटी और चावल के साथ खायी जा रही है। इस तरह से यहां पर इतनी महंगाई है।

आज हमारे शान्ता कुमार जी बोल रहे थे कि 6 लाख करोड़ से 13 लाख करोड़ कमाने वाले एक सौ लोग इस देश में पड़े हुए हैं, उन पूंजीपतियों को पकड़ने का काम आपने क्यों नहीं किया। ऐसे पूंजीपति जो 6 लाख से 13 लाख करोड़ तक आपकी सरकार में चले गए, पिछले पांच साल से वे लोग कमा रहे हैं। दिन रात अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आने वाले दिनों में देश आपको माफ नहीं करने वाला है। जो इस देश में हो रहा है, आप महंगाई बढ़ाकर जो गरीब को मारना चाहते हैं, गरीबों को जो सताना चाहते हैं, वह सारा देश देख रहा है। आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा, इस पर आपको विचार करना चाहिए। आने वाले समय में जनता आपसे इस पर हिसाब मांगेगी, इस पर भी आपको सोचना और समझना चाहिए। महोदय, सदन में महिला आरक्षण विधेयक पेश होने वाला है, राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इस संबंध में बोला गया है। उस महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी-अभी हमारे सदस्यों ने कहा कि इस देश में शिक्षा की दोहरी नीति है, इस देश में स्वास्थ्य की दोहरी नीति है।

इस देश में खानपान की दोहरी नीति है, इस देश में रहन-सहन की दोहरी नीति है। इस देश में कुछ लोगों को काम के आधार पर, जाति के आधार पर बांट दिया गया है। उनको जाति के आधार पर क्यों बांटा गया है? जाति के आधार पर कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई खेत में काम करने वाला है, कोई मछली मारने वाला है, कोई मोची का काम करने वाला है, कोई जूता साफ करने वाला है, कोई कपड़ा साफ करने वाला है, ऐसे लोगों को जाति के आधार पर, काम के आधार पर बांटा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि जब तक जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक आपको आरक्षण में आरक्षण करना पड़ेगा। आप महिला विधेयक लाने वाले हैं, इसमें भी दलित और अत्यंत पिछड़ा, महादलित है, इस पर भी आपको विचार करना होगा। हमारी एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, उसका एक फार्मूला है, नीतीश फार्मूला। आप 33 परसेंट आरक्षण की बात करते हो, मैं कहता हूं कि महिलाओं के लिए 50 परसेंट आरक्षण कीजिए । बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण का फार्मूला लागू किया है, वहां पर 50 परसेंट आरक्षण दिया गया है, उसमें सारे वर्गों को, दलितों को, पिछड़ों को, अत्यंत पिछड़ों को, महादलित को आरक्षण दिया है। जो आरक्षण

का नीतीश फार्मूला है, जिसको पंचायत स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में चलाने का काम किया है और उसको मान लिया है। जो नीतीश जी का फार्मूला को मानकर आपने पूरे देश में किया है, उसी फार्मूले के अंतर्गत जब तक आप महिला आरक्षण बिल नहीं लायेंगे, तो एक क्रांति होगी। इस देश को क्रांति में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यह जो महंगाई की मार है, आतंकवाद की मार है, नक्सलवाद की मार है, गरीबों को ठगने का काम है, गरीब को मरवाने का काम है, महंगाई की आग में यदि आप आग में घी डालने का काम करेंगे, तो अच्छा नहीं होगा। आप को महिला आरक्षण में दलित और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई चुप बैठेगा, तो उसके लिए लोग यही कहेंगे:-

"समर शेष नहीं पाप का, भागी केवल व्याध है,
जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध।"

जो तटस्थ रहेगा, उसका भी अपराध लिखा जाएगा कि आने वाले दिनों में जो आरक्षण हो रहा है, उसमें दलित, महादलित, शोषित और उपेक्षितों की बात नहीं रखी गई, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं:-

"गंगा की कसम, जमुना की कसम,
यह तानाबांना बदलेगा,
कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें,
तो सारा जमाना बदलेगा।"

जय हिन्द, जय भारत। मैं उपसभापति महोदय को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय से एक मिनट ज्यादा टाइम मुझे बोलने के लिए दिया। मैं तो अपनी बात नौ मिनट में ही खत्म करना चाहता था, मगर आपने जो ज्यादा समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): सर, आप हमारे बिहार की आवाज देखते हैं, हर आवाज दब रही है।

श्री उपसभापति: देख रहे हैं। श्री खेकिहो झिमोमी, श्री अहमद सईद मलीहाबादी, श्री अवनि राय, श्री राजीव चन्द्रशेखर, श्री प्यारीमोहन महापात्र अनुपस्थित। श्री मंगल किसन।

श्री मंगल किसन (उड़ीसा): उपसभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपसभापति: आपके पास बोलने के लिए सात मिनट का समय है।

श्री मंगल किसन: ठीक है। सर, हमारी पार्टी छोटी है और आप आखिरी में बोलने का मौका देते हैं।

श्री उपसभापति: आपकी पार्टी छोटी नहीं है, आपको भी ज्यादा समय मिलेगा। आप अदर्स में आते हैं, तो बड़ी पार्टी हैं।

श्री मंगल किसन: सर, राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में सरकार का जो कार्यक्रम है, 74वें पैराग्राफ में सरकार की जो नीति है, सरकार की जो कार्यक्रम है, उसको सदन में रखा है। इसके साथ-साथ देश के अंदर जो समस्या है, उस समस्या को भी राष्ट्रपति महोदया ने सदन में रखा है। वह समस्या क्या है — internal security problem in the country; crossborder terrorism and naxalism in the country; the drought situation in the country; price-rise of essential commodities in the country, law and order problem in the country, and, increase in incursion of terrorists across the border in Jammu and Kashmir.

The steps to unearth the unaccounted money outside the country, the Government is having talks with the Switzerland Government to bring that back black money to the country. सर, विशेषकर यह जो नक्सली समस्या है, इसमें हिन्दुस्तान का 1/3 एरिया नक्सलिज्म के ऑपरेशन एरिया में

आ चुका है और सही ढंग से कहा जाए, तो एक तिहाई एरिया में करीब 160 से 170 जिलों में नक्सलिज्म और नक्सलियों का शासन चल रहा है। भारत सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट गवर्नमेंट के एफेक्टेड एरिया में हैं, Police is completely inactive और दूसरी बात यह है कि यह नक्सलिज्म और टेररिज्म 15 साल से ज्यादा समय से चल रहा है। नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी ताकत नहीं है, जो इसको अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से कंट्रोल कर सके। नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार जो ढुलमुल नीति अपना रही है, उसको क्लियर करना चाहिए। Whether the Naxalism is being controlled by the Government of India with the help of the State Governments, that should have complete thinking and decision of the Government. तब जाकर कुछ हो सकता है। कभी बोलते हैं कि हम फोर्स भेजते हैं, कभी बोलते हैं कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश के सिस्टम को बचाने के लिए, देश के समाज को बचाने के लिए सरकार को स्ट्राँग होना पड़ेगा और इसके खिलाफ स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। हम सभी लोग बोलते हैं कि गरीब जनता का काम करने के लिए देश के पास, सरकार के पास धन नहीं है। इसके चलते 30 करोड़ से ज्यादा जो आम जनता गरीबी रेखा से नीचे है, उसके उत्थान के लिए आजादी के 63 साल बाद भी सरकार के पास कोई ऐसा कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम नहीं है, जो पीछे वालों को आगे वालों के समान कर सके। Due to lack of funds सरकार लाचार है, मगर देश के अंदर जितनी भी ब्लैक मनी है, जितनी भी अन-एकाउंटेड मनी है, उसको निकालने के लिए 63 साल के अंदर ठोस कदम उठाकर आम जनता के काम में लाने के लिए, देश के काम में लाने के लिए, अभी तक सरकार नहीं सोच रही है। इसका मतलब यह है कि जो अन-एकाउंटेड मनी है, यह जहां पर है, सरकार को मालूम है, मगर इसको निकालकर देश के काम में लगाने के लिए सरकार की नीति और मन ठीक नहीं है। इसी हिसाब से एक रिपोर्ट आई है, Bank Association of Switzerland. वे रिपोर्ट में दे चुके हैं कि सबसे ज्यादा पैसा हिन्दुस्तान का स्विटर्जलैंड में है। यह सब अखबारों में आ चुका है। उस पैसे को, उस धन को देश के काम में लाने के लिए सरकार को स्ट्राँग होना पड़ेगा।

अपने मन को, अपनी नीति को ठीक करना पड़ेगा। खाली आम जनता को खुश करने के लिए, सिर्फ वे लोग जब बोलेंगे कि we will bring back the unaccounted money from abroad. ऐसा बोलने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। सरकार की सही मंशा होनी चाहिए। सर, विशेषकर जो समाज की आखिरी लाइन में हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वह जो संप्रदाय है, वे लोग आज से नहीं, बल्कि आजादी के पहले से शोषण का शिकार होते आ रहे हैं। अभी भी आजादी के 63 साल बाद भी उनका इकॉनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली कोई व्यापक चेंज नहीं हुआ है। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: समाप्त हो गया है। सात मिनट हो गए हैं, प्लीज कंक्लुड।

श्री मंगल किसन: सर, सरकार को इन ग्रुप्स को, जो पिछड़े हैं, उनको साथ रखकर देश के समुन्नित विकास के लिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड): आदरणीय उपसभापति जी, मैं जब पिछली बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ - जयंती जी यहां नहीं है, वे कुर्सी पर थीं, उनको थोड़ा एतराज था, इसका कारण एक ही था कि मैंने कहा कि मैं भी जानता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का दस्तावेज होता है, लेकिन इसमें कहीं एक वाक्य तो ऐसा होना चाहिए, जिससे यह लगे कि यह राष्ट्रपति की ओर से देश को कोई संदेश जा रहा है। वह शायद हिंदी कम समझती हों, वे नहीं समझ पाईं, लेकिन मैंने बाद में इसको क्लियर किया था। आज मुझे थोड़ी सी खुशी होती है कि कम से कम आखिर के पेज में, हमारे दोनों वक्ताओं ने इसको पढ़ा है, हमारी नजमा जी और शांता कुमार जी ने 74वें पैरा के बारे में कहा, हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, मैं आगे पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा लगता है कि शायद सोच में पिछली बार से परिवर्तन आया है, दृष्टि में कुछ परिवर्तन आया है। मैं पहले उसके आगे की पंक्तियों से कहूंगा, उसको

अंत में लूंगा, भारत के पं. नेहरु जी के 14 अगस्त, 1947 के कथन से उद्धृत करते हुए कहा गया है, "भारत की सेवा का अर्थ है, उन करोड़ों लोगों की सेवा, जो पीड़ित है।" इसका अर्थ है "गरीबी, अज्ञान और अवसर की असमानता को समाप्त करना।" हमारे पूरे सदन में सभी सदस्यों ने इस पर बोला है, मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि सदन में कल ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भारत में इस समय 30,17,00,000 लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। मैंने अन्य संस्थाओं के सर्वे, आकलन पढ़े हैं, उनके हिसाब से दस मिलियन यानी पचास करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हम बहुत बार कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया। अगर आप पूछें कि गरीबी की रेखा की परिभाषा क्या है, तो मैं नहीं सोचता कि आप बता पाएंगे या मैं बता पाऊंगा, लेकिन मैं एक अत्यंत ही गरीब के द्वारा, उसकी जो परिभाषा बताई गई है, वह इस सदन में बताना चाहता हूं। आज से दो-तीन साल पहले मुझे एक अत्यंत ही गरीब मजदूर मिला। वह कहने लगा कोश्यारी जी, आप सभी लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करते हो, क्या आप गरीबी की रेखा की परिभाषा दे सकते हो? मैंने कहा, मैं नहीं दे सकता। गरीब मैं भी था, पर अब मैं अच्छे कपड़े पहनने लग गया हूं और अब पार्टी ने भी आगे बढ़ा दिया है, शायद मैं नहीं दे सकता, पर तू गरीब है, तू बता। वह कहने लगा कि देखिए, मेरे पड़ोस वाले ने मकान बनाने के लिए सरकार से दस-बारह हजार रुपए का कर्जा लिया था। वह सस्ते ब्याज पर था। वह कर्जा वह परिवार वाला दे नहीं पाया। एक दिन ऐसा आया कि निश्चित रूप से उसकी कुर्की हो गई, जब उसके जेल जाने की बात आई, तो वह हार्ट फेल से मर गया और वह गरीबी की रेखा से ऊपर, बहुत ही ऊपर चला गया। यह उस गरीब ने गरीबी की रेखा के बारे में कहा है। आज हम जिस गरीबी की रेखा की बात कर रहे हैं, वह गरीबी की रेखा वास्तव में क्या है? केवल इसलिए कि जिसको बीस रुपए मिल रहे हैं, अभी बता रहे थे कि रोज उससे ज्यादा मिलता नहीं है, वास्तव में आज देश के अंदर जो गरीबी की हालत है, मैं सोचता हूं कि, हम सभी के लिए, मैं यह नहीं कहता कि केवल सरकार के लिए शोचनीय है।

नजमा जी कल बहुत अच्छी बात बोल रही थीं कि आखिर सरकार में जो हमारे लोग बैठे हैं, वे विपक्ष को बुलाते क्यों नहीं है, दूसरे लोगों को बुलाते क्यों नहीं हैं? सरकार चलाने का काम केवल सरकार का ठेका तो नहीं है। हम सब मिल कर उस गरीब के लिए, जिसने मुझे गरीबी की परिभाषा दी है, इस देश के गरीब आदमी ने इस प्रकार की परिभाषा दी है, क्या हम उसे दूर कर सकते हैं? क्या वास्तव में हम गरीबी दूर कर सकते हैं? मैं यह नहीं कहता कि आजादी के बाद देश के अन्दर prosperity नहीं बढ़ी है। मैं यह भी नहीं कहता कि देश के अन्दर विकास के काम नहीं हुए। मैं यह भी नहीं कहता कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या हम उस दिशा में वास्तव में एक प्रकार से नीचे जाकर सोच रहे हैं, क्या वास्तव में उनसे एकात्म होकर सोच रहे हैं? अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि हमारे कोई राजनेता कलावती के यहाँ एक दिन चले गए। जो कलावती के यहाँ चले गए, उनको तो सुनते हो, लेकिन जो कलावती के घर में पैदा होकर वीर सिंह जैसे यहाँ आए हैं, पले हैं, बढ़े हैं, जिन्होंने देखा है, उनको भी तो सुनो ना! उनकी ओर तो आप ध्यान ही नहीं देते हो। कोशिश यह करनी चाहिए कि वास्तव में इस देश के अंन्दर जिन्होंने उसको नजदीक से भोगा है, देखा है, उनको भी सुना जाए कि इस देश को कौन सी दिशा देना चाहते हैं।

जब हम गरीबी पर विचार करते हैं, महंगाई पर विचार करते हैं, तो निश्चित रूप से इस देश के अन्दर जो विचार करने वाले हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ चाहे आपकी केन्द्र सरकार हो, चाहे हमारी प्रदेश सरकार हो, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, यदि आपने विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया है, आप गहराई तक जनता के बीच गए नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस गरीबी की परिभाषा केवल वह करता है, जो इस हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके आता है, जो इस हिन्दुस्तान को चलाता है। मुझे ध्यान है कि जिस समय 1977 में शान्ता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और भैरों सिंह शेखावत जी राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, पहली बार इन्होंने अन्त्योदय की जो योजना चलाई, मैं आज भी जानता हूँ कि दुनिया के अखबारों ने उसकी प्रशंसा की थी कि अन्तिम छोर पर बैठे आदमी को उठाने के लिए काम किया गया है। मैंने इसकी कटिंग रखी है, अगर आप

कहें तो मैं इसे ला सकता हूँ। वास्तव में हमारा कोई साफ दृष्टिकोण तो हो। हम जो जीवन जिए हैं, क्या हम उसमें जाना चाहते हैं?

मेरे सामने माननीय विदेश मंत्री जी बैठे हैं। पिछले दिनों मैंने उनको नेपाल के बारे में कुछ बात कही, क्योंकि मैं उसके नजदीक रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे मुझसे बहुत विद्वान हैं, अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि उनकी इसमें जिज्ञासा होती कि यह हमारे पड़ोस का देश है, तुम उसके नजदीक रहते हो। उनकी ओर से अगर हम लोगों को invitation आता, तो शायद उसका कोई अर्थ होता। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अन्दर एक पीड़ा होती है, एक दर्द होता है, वह दर्द कम हो गया है। वह दर्द तब होता है, जब हम उसको जीते हैं, उसके साथ रहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में हमने पंडित नेहरू जी को याद करके आज जो कहा है और जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आया है, यह आगे के लिए एक प्रकार से हमारे लिए गाइडलाइन हो जानी चाहिए। आपने ऊपर जो आह्वान किया है, मैं उसे बाद में बोलूँगा। लेकिन अगर हम सब इसको नहीं करेंगे, तो कागज में उसे लिख लिया, कल उसे भूल गए, तो मैं नहीं सोचता कि इस देश से गरीबी हटेगी या हम इसकी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे।

मान्यवर, अभी सुबह यहाँ कृषि मंत्री जी बैठे थे। मैं महंगाई पर ज्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सब लोग इस पर बोल चुके हैं। मैं केवल इतना निवेदन करता हूँ, लोग बहुत आँकड़े दे रहे थे, मैं आँकड़ों के मकड़जाल में नहीं पड़ना चाहता, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि इस देश के अन्दर 50 रुपए में आप जितना चाहें, उतनी चीनी मिल सकती है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यह 25 रुपए में नहीं मिलती है। मुझे ध्यान है कि जब 1977 में जनता पार्टी का शासन आया था, तब 9 रुपए या 10 रुपए किलो चीनी थी, वह घट कर 2 रुपए किलो हो गई थी। दुर्भाग्य से वह सरकार गिर गई, लेकिन जब तक वह सरकार रही, वही 2 रुपए किलो चीनी बिकती थी। पिछले एनडीए शासन में भी ऐसा ही था। कहीं-न-कहीं हमें सोचना चाहिए कि चीजें हैं, उस समय शरद जी कह रहे थे कि अन्न का भण्डार है, सब कुछ है, जब अन्न का भण्डार है, तो भई, तुम कैसे भण्डारी हो कि जैसे कल उत्तर प्रदेश में यह दुर्भाग्य रहा कि एक साधु लोगों को भण्डारे में 20 रुपए दे रहा था, उस 20 रुपए के लिए 65 लोगों की जान चली गई और आपका भण्डार भरा है।

लेकिन आज स्थिति यह है कि लोग यहां भूखे मर रहे हैं और 20 रुपये के पीछे अपनी जान दे रहे हैं। आखिर यह क्या स्थिति है? यहां पर सवाल आपका या मेरा नहीं है, सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है। यह बड़ा ही वाइटल क्वेश्चन है। मैं सोचता हूं कि हम सब लोगों को कहीं न कहीं इस पर विचार करना चाहिए कि मात्र 20 रुपये, एक लोटा और एक गिलास लेने के लिए 70-80 लोगों की जान चली जाती है और दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी कहते हैं कि भंडार भरे हुए हैं। अब चूंकि शरद जी के तो सभी भंडार भरे ही हुए हैं, इसलिए वे तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हमारे यहां पर कहते हैं कि जिसको दोनों आखें नहीं होती है, उसको सावन में सब हरा-हरा ही दिखता है, इसलिए लगता है कि उनको सब जगह हरा ही हरा दिख रहा होगा और भंडार ही भंडार दिख रहे होंगे। हमें इस विषय पर सोचना चाहिए। आप इस विषय के संबंध में उनके स्तर पर जाकर सोचें, जिससे आप गरीबी दूर कर सकें, इस महंगाई को दूर कर सकें, लेकिन उसके लिए आपको पहले उस स्तर पर जाना होगा।

मान्यवर, अभी हमारे शान्ता कुमार जी भ्रष्टाचार पर काफी बोले हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि यह कैसा दुर्भाग्य है कि जीप कांड से लेकर मुद्रा कांड एवं कोडा कांड जैसे न जाने कितने ही कांड हो चुके हैं और न जाने कितने ही राजनेताओं से जुड़े हुए कितने ही कांड सुने जा चुके हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश के अन्दर आज भ्रष्टाचार की बीमारी इतनी बुरी तरह फैल रही है कि इस देश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और देश के लैफ्टिनेंट जनरल पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि मिलिट्री के एक सैनिक अधिकारी को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल हो गई, और तो

और पोस्ट मास्टर जनरल को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल हो रही है। इस तरह आज यह एक बीमारी बन चुका है। इसके बारे में हमें अवश्य ही कुछ सोचना होगा, ले किन यह काम केवल भाषण से नहीं होगा। यह काम न तो मेरे भाषण से होगा और न ही आपके भाषण से होगा। कहीं न कहीं कुछ मूलभूत चीजें और बीमारियां हैं, जो देश को बुरी तरह नष्ट कर रही हैं।

हमारे वीर सिंह जी के यहां अगर हाथी कम हो जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इससे पड़ेगा कि कहीं न कहीं हम इस समस्या का निदान करें और असली बीमारी को डायग्नोज़ करें। हम बीमारी को तो डायग्नोज़ कर नहीं पा रहे हैं, तो उसका इलाज कहां से कर पाएंगे? इसका इलाज हम बस ऊपर ही ऊपर से करने जा रहे हैं। आजादी के समय हमारी जितनी आबादी भी नहीं थी, उतने तो आज हमारे यहां पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले, बीपीएल कैटेगरी वाले लोग हैं। आखिर यह स्थिति क्यों है? इस पर कभी हम सभी को बैठ करके अवश्य सोचना चाहिए। मुझे याद है, कुछ दिन पहले यहां पर जयराम जी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहां के विषय में जानते हो, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मुझे अच्छा लगा। अखिर हम पहाड़ के हैं, पेड़ों के नज़दीक रहते हैं, नदियों के नज़दीक रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको लगा हो कि इनसे बात करनी चाहिए। हम लोगों को एक-दूसरे से बात क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों न हम इस ढंग से काम करें, जिससे हम इस भ्रष्टाचार को यदि पूरी तरह से भले ही खत्म न कर सकें, ज़ीरो पर न ला सकें, लेकिन कम से कम इसमें कुछ कमी तो ला सकें। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज जरूरत इस बात की है कि हम सब लोगों को कहीं न कहीं इन चीज़ों पर दृढ़ता से निश्चय करने होंगे।

मान्यवर, अभिभाषण में आपने अपनी सरकार की ओर से बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, यह रूटीन भी है, लेकिन मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे एक निवेदन अवश्य करता हूं, आपने कहा है कि हम मिशन बनाएंगे। आपने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बनाया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन बनाया, यहां लोग मरते जा रहे हैं और आप खाद्य सुरक्षा मिशन बनाने की बात कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन बनाया, ऊर्जा पर तो आठ-आठ मिशन बनाए गए, सौर ऊर्जा के लिए भी जाने क्या-क्या हुआ। इतने मिशन बने हैं। बहुत अच्छी बात है, आप मिशन बनाइए, अच्छा लक्ष्य रखिए, लेकिन कितने भी मिशन आप बनाते जाओ, केवल मिशन बनाने से काम होने वाला नहीं है। मिशन के साथ-साथ you must have got missionaries.

महोदय, जब तक काम करने वाले मिशनरीज़ नहीं होंगे, सेवाभावी लोग नहीं होंगे, तब तक कैसे काम चलेगा? हमारे यहां पर क्रिश्चियन लोगों के लिए कहते हैं कि मिशनरी आ गए। कितनी सेवा भाव से काम करके उन्होंने यहां पर कन्वर्जन किया है। यह काम उन्होंने सेवा से किया है, जबरदस्ती तलवार से नहीं किया है। आखिर सेवा भाव वाले को ही मिशनरी कहते हैं, लेकिन हममें वह मिशनरी भाव कहां है? वह सेवा भाव कहां है? जब माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे, तब पहली बार उन्होंने कहा था कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे और उस समय बनाई गई प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना आज भी है। मैं आपकी सरकार को बधाई देता हूं कि आपने उस योजना को जारी रखा है। वे चाहते थे कि 2012 तक हर गांव को कच्ची सड़क से नहीं, पक्की सड़क से जोड़ें। मैंने 1971-72-73 की सड़कें देखीं हैं, वे आज कहां हैं, लेकिन आज तब की बनाई सड़कें बनी बाद में हैं और टूट पहले गई हैं। उन्होंने कहा था कि हम सड़क बनाएंगे, पक्की सड़क बनाएंगे। यह आश्वासन कौन दे सकता है? यह आश्वासन वही दे सकता है जिसने भारत के हर गांव को देखा हो। राहुल बजाज जी चले गए, यह आश्वासन वही दे सकता है जिसने भारत के गांव के छोटे से छोटे गरीब से लेकर राहुल बजाज जैसे लोगों तक, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ देखा हो। ऐसा व्यक्ति ही तो अच्छी-अच्छी योजनाएं लाएगा।

नीचे से लेकर ऊपर तक, वही तो अच्छी योजनाएँ लाएगा। मेरा जो विधान सभा क्षेत्र रहा है, वहाँ मैंने उस योजना के अंदर कम से कम 50 किलो मीटर सड़क एक ही साल में बनवायी है, क्योंकि उसके लिए पैसा था, उसके लिए व्यवस्था थी। यह योजना क्यों नहीं पूरी हो रही है? वह कोई अटल जी की या एन.डी.ए. की

योजना नहीं है, वह आपने भी चला रखी है। हम 2012 तक हर घर को बिजली देंगे, हर घर में एक बल्ब लगाएँगे, वह क्यों पूरा नहीं हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग कहीं न कहीं उस ओर इतने गम्भीर नहीं हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर काम चल रहा है तो क्या करना है, काम तो चल ही जाएगा। काम चलाने के हम नये-नये रास्ते ढूँढ़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम "गरीबी हटाओ" का नारा लगाएँगे तो यह हो जाएगा। अगर हम "आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ" बोल देंगे तो काम चल जाएगा। यह थोड़े दिनों तक तो चलेगा, लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा?

उपसभापति जी, यहाँ परसों कुरियन साहब का भाषण हो रहा था। अपने कक्ष में बैठ कर मैंने पूरा एक घंटा उनका भाषण सुना। उन्होंने अपने भाषण में एक बहुत अच्छी बात कही कि यह जो हिन्दू है, इसको मैं केवल religion नहीं मानता, बल्कि इसको मैं एक culture मानता हूँ। ये रवि शंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने इसे way of life कहा है और उन्होंने इसको culture कहा है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, वह मैं आपको बता रहा हूँ। कुरियन साहब ने बहुत ही सुन्दर बात कही। उन्होंने कहा कि आज से सैकड़ों साल पहले, जब भारत में ईसाई आये तो उस समय उनके गांव के बगल में कुछ ईसाई किसी अपने के मृत शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए कहीं दूर कब्रिस्तान ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ कब्रिस्तान की जगह नहीं थी। उसे वहाँ के राजा ने देखा। उस राजा ने पूछा कि इसे कहाँ ले जा रहे हो तो उसने कहा कि हम इसे यहाँ से 20 मील दूर ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसे दफनाने के लिए हमें जगह नहीं मिली है। इसी सदन में कुरियन साहब ने यह बयान दिया है। उस राजा ने कहा कि अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? यह जो गांव है, इसी के बगल में मैं तुम्हें जमीन दे देता हूँ। वहाँ मन्दिर के बगल में उसे जमीन दे दी गयी। वहाँ आज भी यह सब चल रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जब Jews आये तो हिन्दू राजा ने उन्हें जगह दी और जब मुस्लिम आये, इस्लाम आया तो उन्हें भी हिन्दू राजा ने वहाँ जगह दी। यह कुरियन साहब का बयान है। यह मेरा बयान नहीं है। यह इसी सदन में दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि Christianity यूरोप से पहले हिन्दुस्तान में आयी। उनको भी हिन्दू राजा ने जगह दी - रिबैलो जी, आपको खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें हिन्दू राजा ने जगह दी।

माननीय उपसभापति जी, मैं आपसे और इस पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कुरियन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उनकी बात से अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता हूँ, लेकिन क्या यह one-way traffic नहीं है? एक पंथ के मानने वाले ने तो सब लोगों को आने की इजाजत दी और दूसरे पंथ के मानने वाले केवल एक मन्दिर के लिए जगह नहीं देंगे, तो इस देश के अंदर कौन-सा भाव पैदा होगा, यह आप लोग सोच लीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप सभी सम्मानित सदस्य हैं, सभी देशभक्त और राष्ट्रभक्त हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक तो सभी के लिए जगह दे रहा है और आप क्या एक मन्दिर के लिए भी जगह नहीं दे सकते, एक मन्दिर के लिए अपने को उदार नहीं बना सकते? तो ये उदारता, ये one-way traffic may go wrong. आप लोग यह बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर आप अवश्य सोचेंगे और इस पर आपका ध्यान जाएगा।

दूसरा, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि कम से कम कुरियन साहब जिस भाव से बोल रहे थे, मैं चाहूँगा कि हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उनका जो लक्ष्य था और उन्होंने जो इसकी प्रस्तावना में लिखा, अगर हम उससे हट कर इस देश के अंदर धर्म के नाम पर आरक्षण देने के पक्ष में हैं तो निश्चित रू प से यह सही नहीं है। मैं किसी वर्ग का द्रोही नहीं हूँ, मेरी दृष्टि में सब में परमात्मा है। अगर कोई भी गरीब है, अगर कोई भी अशिक्षित है, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो या वह किसी भी पंथ का हो, उसका उत्थान होना चाहिए, उसको सहायता मिलनी चाहिए। अगर आप केवल और केवल वोट पर नजर रख कर, केवल और केवल कुर्सी पर नजर रख कर - आपने यहाँ नेहरू जी का उदाहरण दिया, हम बार-बार डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं - अगर आप नेहरू और डा0 भीमराव अम्बेडकर का नाम लें, लेकिन जिस आत्मा के साथ, जिस ध्येय के साथ

उन्होंने संविधान को बनाया और जो बातें उन्होंने संविधान सभा में कही थीं, उनके विरुद्ध अगर आपने निर्णय लिया तो आप यह निश्चित रूप से मानिए कि उनकी आत्मा जहाँ होगी, वह आपको कभी माफ नहीं करेगी, मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब मामलों में आप जरा वोट से ऊपर उठ कर देखिए। इस देश को जोड़िए। इस देश को एक बनाइए। आप केवल वोट को मत देखिए। अब बहुत हो गया। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, मेरा आपसे एक और निवेदन है कि यह हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अभी कुछ लोगों ने इस पर बोला भी है कि हमने इस संसद के अंदर एक प्रतिज्ञा की थी, संकल्प लिया था कि हम इस देश की एक-एक इंच भूमि को विदेशी आक्रमणकर्ताओं से, चाहे उत्तर की ओर से चीन हो या पश्चिम की ओर से पाकिस्तान हो, मुक्त कराएंगे, लेकिन कहां है वह प्रतिज्ञा? आप क्यों उस संकल्प को याद नहीं करते हो? हमने कहा, सारे मीडिया में आ गया, सब जगह आ गया। हमारे पास रिपोर्ट बोलती है, वहां के अधिकारी भी अनऑफिश्यली बोलते हैं, हां-हां उधर से लोग आए और सारा पत्थर लगाकर उन पर लाल निशान लगा गए, लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि नहीं-नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे विदेशी मंत्री, रक्षा मंत्री और न जाने किन-किन के बयान आते हैं। आप सावधान रहिए, ऐसे बयान हमने 1950 से 1960 के बीच में, जब हिन्दुस्तान पर आक्रमण हुआ था, तब सुने थे। तब हमारे देश के स्वनामधन्य प्रधान मंत्री कहते थे कि There does not grow a blade of grass. वहां पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता है और आज आप ऐसा ही बयान दे रहे हैं। आप तैयार रहिए। जो 1962 की स्थिति थी, भगवान करे वह न आए, परन्तु यह सुनिश्चित है कि आखिर चीन आपकी सीमा पर लाखों की सेना इसलिए खड़ी नहीं कर रहा कि उसने फिर से आपसे भाई-भाई के नारे लगाने हैं, आपके हाथ से अपना हाथ मिलाना है, बल्कि वह इसलिए कर रहा है कि उसका लक्ष्य इस दुनिया के अंदर अपना राज स्थापित करना है, शासन स्थापित करना है और वह भारत को एक stepping stone के रूप में बनाना चाहता है, इस पर हम सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज इस सदन के माध्यम से निश्चित रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आखिर चीन इतना आगे बढ़ गया और हमारे यहां क्या हो रहा है।

उपसभापति जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा जिला पिथौरागढ़ भी पड़ता है, जो नेपाल से लगा है। आप ताज्जुब करेंगे कि हमारे यहां बार्डर रोड जो सेना के अंडर है, मैंने उस दिन रक्षा मंत्री जी को बताया भी था, यानी चाइना की सीमा की तरफ से सड़क आ गई, वहां से नीचे सड़क बना रहे हैं। शान्ता कुमार जी को अभी पता हैं या नहीं हमारे यहां हेलिकॉप्टर से जे.सी.बी. उतार कर ऊपर से नीचे की ओर सड़क बनाई जा रही है नीचे 50 किलोमीटर सड़क बननी है, पर चीन की सीमा से नीचे की ओर सड़क बनाई जा रही हैं यानि उल्टे बांस बरेली। ताकि चाइना वालो जब तुमको जरूरत हो सीधे आ जाओ, मानो हमारा हाथ इसी वजह से तुम्हारे हाथ में आने के लिए तैयार है। इसीलिए क्या सड़क वहां ऊपर से नीचे बन रही है? मैंने बोला कि ऐसे लगता है कि नक्कारखाने में तूते की आवाज। एक मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, जो पूर्व मुख्य मंत्री रहा हो, लेकिन उसकी बात पर कोई कार्रवाई ही नहीं होती है! इसका सीधा अर्थ है कि हम निश्चित रूप से गंभीर नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह शतुरमुर्गी चाल बंद करनी चाहिए। शतुरमुर्ग की तरह से अगर सिर नीचे बालू में छिपाओगे तो फिर वही हाल होगा जो 1962 में हुआ। आपका जो होगा सो होगा, लेकिन सारे देश का क्या होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो प्रस्ताव संसद ने पास किया है कि हम एक-एक इंच भूमि वापिस लेंगे, मैं सोचता हूं कि हम हर साल जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ते हैं, मैं तो कहता हूं कि हर साल सदन शुरु होते ही पहले दिन आप उस संकल्प को पढ़िए, जो संकल्प इस सदन ने किया था, ताकि हमको याद रहे कि हमारा लक्ष्य क्या है। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा

था कि चीन का रक्षा बजट हमसे दुगुना हो गया है। वह हमसे दुगुना रक्षा बजट रख रहा है, पहले ही वह इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस बारे में, हमारी उस बारे में क्या पॉलिसी है? क्या शार्ट टर्म पॉलिसी है, क्या लॉंग टर्म पॉलिसी है?

मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के चारों ओर की स्थितियां, चाहे वह नेपाल हो, बंगला देश हो या दूसरे देश हों और यहां तक कि पाकिस्तान, मैं पिछली बार UNO में गया था, वहां हमारे साथी ने, वहाँ के permanent representative से अंग्रेजी में परिचय कराया। मैंने कहा आप थोड़ा हिन्दी तो समझते हो न? ऐसा नहीं है, कपिल जी, I also know a little bit of English. When you speak in English I can also understand it. मैंने कहा कि साहब आप तो हिन्दी जानते होंगे। उसने कहा कि क्यों नहीं, आप तो पड़ोसी हो, आओ, गले मिलो।

श्री रवि शंकर प्रसाद: उपसभापति जी, कोश्यारी जी अंग्रेजी के शिक्षक रहे हैं, वे बोल नहीं रहे हैं। यह उनकी humility है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : वे मेरे गले मिल गए और मेरे साथ throughout हिन्दी में बोले, उनकी उर्दू मिश्रित हिन्दी भाषा इतनी सरल थी कि मुझे लगा कि वे मेरे ही देश के हैं। सवाल यह है कि आखिर हम सब एक थे। आज हम इस स्थिति में हैं कि वे हमारी ओर देख रहे हैं, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम अपनी ही चिंता नहीं कर रहे हैं, हम अपने को ही संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या संभालेंगे? मैं सोचता हूं कि इस पर तत्काल बड़ी गंभीरता से विचार होना चाहिए।

उपसभापति जी, मैं आपसे एक और निवेदन उत्तराखंड के बारे में करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं और उत्तराखंड के बारे में यदि मैं नहीं बोलूंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमारे सामने बजट पेश किया गया, बजट पर शायद मैं न बोलूं, इसलिए यहां पर बोल रहा हूं। हमारी सरकार की कैसी सोच है, वैसे कैबिनेट में आप एक साथ मिलकर सोचते हो, पहले कहा गया कि सिक्किम, उत्तराखंड और आसाम, इन तीनों ने, "they graduated ....", अंग्रेजी में एक शब्द है - graduated, I don't know what does this mean. वैसे ग्रेजुएट तो शिक्षा में पैदा होते हैं। खैर, नए-नए शब्द आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उत्तराखंड को अगले 3 साल के लिए एक हजार करोड़ रुपए दे दो, आसाम और सिक्किम को भी 300-300 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि एक हजार करोड़ रुपया तो अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया और उससे पहले जो 5,000 करोड़ रुपया हमें राजस्व घाटे में मिलता था, उसे वे खा गए, खत्म कर गए, पता नहीं कहां ले गए? यही हाल हिमाचल प्रदेश का है।

मैं शान्ता कुमार जी से पूछ रहा था, उनको भी राजस्व घाटे का जो पैसा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला, आखिर क्यों नहीं मिला, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। उत्तराखंड, हिमाचल यह मध्य हिमालय है क्यों नहीं इनके साथ पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर की तरह से बर्ताव किया जाता है, क्यों नहीं इन राज्यों को भी उनके समान सहायता दी जाती है? तब उत्तराखंड में BJP की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, नारायण दत्त तिवारी जी ने भी कहा, हम लोगों ने भी कहा कि उत्तराखंड को स्पेशल औद्योगिक पैकेज दीजिए, उन्होंने स्पेशल औद्योगिक पैकेज दिया, लेकिन हुआ यह है कि हमारी वर्तमान सरकार ने पहले तो उस स्पेशल औद्योगिक पैकेज को 2007 तक खत्म कर दिया, जब कि वह पैकेज हमें 2013 तक के लिए मिला था। हम लड़े, कांग्रेस के लोग भी लड़े कि जब हमें यह पैकेज 2013 तक के लिए दिया गया था, तो आप दिया हुआ वापस क्यों ले रहे हैं? जब आप पहले दिया हुआ वापस ले रहे हैं, तो फिर आप हमारा क्या भला करेंगे? इसलिए मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को फिर से औद्योगिक पैकेज दिया जाना चाहिए। जो पैकेज पहले भाजपा के समय में दिया गया था, उसे फिर से दिया जाना चाहिए।

उपसभापति जी, मैं अंत में एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण के अंतिम पैरा में लिखा है कि – "हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्र

निर्माताओं ने राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के हम इतने करीब पहले कभी नहीं थे।" मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं। मेरे सामने वेंकैया जी बैठे हुए हैं, दूसरे बड़े नेता भी हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत छोटे कार्यकर्ता के रूप में आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी मेरी बात से कहीं भी असहमत नहीं होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री बहुत अच्छे, ईमानदार आदमी हैं, बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन परसों जब आडवाणी जी बोल रहे थे, तो मैं संयोगवश टी.वी. पर देख रहा था, मुझे बहुत दुःख हुआ कि प्रधान मंत्री जी जैसे धैर्यवान और शांत आदमी, जिनकी हम दूसरी जगह प्रशंसा करते हैं कि वे कितने शांत हैं, कितने गंभीर हैं, लेकिन परसों ऐसा लगा कि वे अपनी serenity and gravity, सब कुछ खो बैठे और आडवाणी जी के बोलने पर वे अत्यंत उद्वेलित हो उठे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं उनकी पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको कुछ खतरा लग रहा हो ...**(व्यवधान)**... अगर ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी तो इतने गंभीर हैं, फिर उस दिन ऐसा कैसे हो गया? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आ रहा था। बाहर ही हमारे अध्यक्ष जी ने लिखा है, वैसे यह नारा हम सबका है, कार्यालय के अंदर घुसते ही मोटे-मोटे अक्षरों में यह लिखा है कि – "देश पहले, पार्टी उसके बाद, मैं सबके बाद में।" जब तक हम इस विचारधारा पर नहीं चलेंगे कि सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद मैं हूं, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि निश्चित रूप से इस देश के लिए आपने जो सपना देखा है, आपने अभिभाषण में जो कहा है कि देश इस मोड़ पर खड़ा है, जो आपने बोला है, यह कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसको जैसा लिखा है, जैसा बोला है, वैसे ही करने के लिए फिर उतना ही त्याग करना पड़ेगा।

जो 1947 से पहले हमारे नेता करते थे, उस त्याग को आपको दिखाना होगा। And Charity begins at home. अगर आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो उदाहरण आपकी ओर से आना चाहिए ...**(समय की घंटी)**... । मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने उदाहरण प्रस्तुत किया, तो निश्चित रूप से इस देश को महान बनाने के लिए, इस देश को जगत गुरु बनाने के लिए हम सब आपके साथ होंगे। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री नरेन्द्र बुढानिया। आपके पन्द्रह मिनट हैं।

श्री नरेन्द्र बुढानिया (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। सदन में यह मेरा पहला भाषण है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रो. पी. जे. कुरियन साहब ने जो मोशन किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। सर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने हम सबसे उम्मीद जताई है कि हम सब मिलकर काम करें। इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए सब एक साथ बैठकर सोंचे। हमारे इस देश के गौरव को बढ़ाएं और विश्व समुदाय में भारत को उचित स्थान दिलाएं। यह पूरा विश्व जानता है कि जो पिछला वर्ष निकला है, वह एक बहुत ही संकट का वर्ष था। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर था और पूरे विश्व में हाहाकार मचा था। आर्थिक हालात चरमरा गए थे। ऐसा लग रहा था कि संसार के अंदर क्या होगा? बड़े-बड़े देश, यहां तक कि शक्तिशाली देश भी इस मंदी के दौर से बच नहीं पाए। अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में भी वहां के बैंक फेल हो गए, वहां की बड़ी-बड़ी कंपनियां फेल हो गई और यहां तक कि बहुत से नौजवान, जो बहुत ही अच्छे काम पर लगे हुए थे, को काम से छुट्टी कर दी गई। इस मंदी के दौर से भारत कैसे बचेगा, इसके लिए भी हम सब बहुत चिंतित थे। लेकिन मैं हमारे नेता और यूपीए के चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी को बहुत ही दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके शानदार मार्गदर्शन में और हमारे प्रधान मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी नीतियों के कारण यह मंदी के दौर से भारत दूर रहा। भारत के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई, जिससे हमारे बैंक बंद हों। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई कि कोई कंपनी बंद हो।

ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं हुई कि किसी कंपनी में छंटनी हो। यह सब बहुत ही सूझबूझ के कारण हुआ है। आज हमारे देश की आर्थिक नीति इस प्रकार से बनी कि हम इन सब चीजों से बच सके। महोदय, चूंकि हमारे देश के अंदर मानसून बहुत खराब रहा, हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं हुई ..

जगह-जगह अकाल पड़ा हुआ था, कहीं बाढ़ आई हुई थी। ऐसे हालात में भी, इन सब चुनौतियों का मुकाबला करते हुए हमारे देश की विकास दर 2008-09 में 6.7 प्रतिशत रही, लेकिन पिछले साल 2009-10 में यह 7.5 प्रतिशत रही। महोदय, यह विकास दर इस बात की सूचक है कि हमारी सरकार ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों को सही ढंग से लागू किया।

महोदय, हमारे सामने महंगाई ज़रूर एक बहुत बड़ा विषय है और हम सब इसके लिए बहुत चिंतित हैं। मैंने सबके भाषण सुने हैं। सभी लोग महंगाई से चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं, लेकिन महंगाई कोई अचानक नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं और उन कारणों पर हमें चिंतन करना चाहिए। सिर्फ यह कहना कि महंगाई बढ़ रही है और उसके लिए सरकार को दोष देना और सरकार पर इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाना, यह ठीक नहीं है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, जिसके लिए सब बातों को छोड़कर सरकार के साथ बातचीत करके हमें उससे निपटना होगा। महोदय, यह नहीं है कि हमारी खाद्य वस्तुओं के ही भाव बढ़े हैं, अभी हाल ही में पेट्रोल व डीज़ल के मूल्य बढ़ाने का हमारे विपक्ष के साथियों ने बहुत ज़ोरदार विरोध किया। महोदय, मैं सन् 1985 से लगातार देख रहा हूं और मैंने सभी बजट देखे हैं, लेकिन कभी भी किसी विपक्षी पार्टी ने बजट पर वॉकआउट नहीं किया। यह इतिहास में पहली बार है कि जब बजट में वॉकआउट किया गया। महोदय, बजट एक ऐसी चीज़ है, जिसमें सरकार द्वारा साल भर में देश में जो काम करना है, जो योजनाएं बनानी हैं, उनका किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, उस पर discussion होता है, विचार होता है और वह हम करते हैं। इसलिए उन्हें वॉकआउट न करके बजट के जो प्रस्ताव हैं, उन पर विचार करना चाहिए।

महोदय, हमारे विपक्ष में बैठे हुए जो साथी हैं, उनकी भी सरकार रही है, एन.डी.ए. की सरकार रही है। उनकी सरकार के कार्यकाल में, पांच-छः साल में कभी मूल्य नहीं बढ़े या भाव नहीं बढ़े, ऐसा नहीं है। उनके ज़माने में भी भाव बढ़े थे - पेट्रोल व डीज़ल के भाव बढ़े और एक बार नहीं, बल्कि 33 बार भाव बढ़े। महोदय, 33 बार पेट्रोल व डीज़ल के भाव बढ़े और मेरे पास आंकड़े भी हैं। मार्च, 1996 में पेट्रोल के भाव 48 प्रतिशत बढ़े, डीज़ल के भाव 112 प्रतिशत बढ़े, केरोसिन के भाव 258 प्रतिशत बढ़े और एल.पी.जी. के भाव 78 प्रतिशत बढ़े। महोदय, यू.पी.ए. के शासन में 2004 से अब तक पेट्रोल में 41 प्रतिशत, डीज़ल में 63 प्रतिशत और पी.डी.एस. केरोसिन में सिर्फ 2 प्रतिशत भाव बढ़े। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि सरकार किसी की भी हो, उसको चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है और जब चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है, तो इस प्रकार के कठिन और कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं।

महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ...**(व्यवधान)**... यह मेरा पहला भाषण है, ज़रा बोलने दीजिए। अभी तो मैं अपनी बात पर आया ही नहीं हूं। डिप्टी चेयरमैन सर, इस अभिभाषण के अंदर ग्रामीण विकास पर विशेष ज़ोर दिया गया है और ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं बनाई हैं।

ये योजनाएं हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, राजीव गांधी आवास योजना - ये योजनाएं हमारे सामने हैं। महोदय, मैं आज सबका भाषण सुन रहा था। नरेगा के ऊपर बात चल रही थी। नरेगा के अंदर जो कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, उनकी बात की जा रही थी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह नरेगा नहीं है, यह रोजगार की क्रांति है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ चलकर गांव के अंदर देखिए। जिन गरीबों के चूल्हे नहीं जल रहे थे, इस नरेगा के कारण उन गरीबों के घरों में चूल्हे जलने लगे। नरेगा ने गरीब की पीठ थपथपाई है। इसमें कमियां हो

सकती हैं। जब कोई योजना लागू होती है, किसी योजना की शुरुआत होती है तो उसमें कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को मिल-बैठकर हमें पूरा करना चाहिए। महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी को और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर इस नरेगा को लागू किया है। नरेगा जैसी योजना के लिए 39 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 हजार 500 करोड़ रुपए किए हैं। महोदय, इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिला और 203 करोड़ person-days पैदा हुए। इस रोजगार क्रांति के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी साथी मिलकर इस योजना को सफल बनाएं, यह हम सबका दायित्व बनता है। महोदय, मैं इसमें एक-दो बातें और जोड़ना चाहता हूं। आज यह योजना किसान के खेत में पहुंची है। आज किसान आपको धन्यवाद दे रहा है कि यह योजना उस तक पहुंची। इस योजना को आज पक्के कामों में बदलने की आवश्यकता है। पक्के कामों में बदलने के लिए इस योजना में 40 प्रतिशत मेटिरियल कम्पोनेंट का प्रावधान है। पक्के काम में बदलने के लिए 70 परसेंट मेटिरियल कम्पोनेंट की आवश्यकता होती है। इसमें जो 30-32 परसेंट का बीच का रेश्यो है, यह हमें किसी अन्य योजना से देना चाहिए। महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

मैं बहुत सी बातों पर बोलना चाहता था। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आज हमारे सामने बहुत अधिक चुनौतियां खड़ी हैं। आज हमें इस प्रकार की बातों का बहिष्कार करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस देश के अंदर आज बहुत सी ऐसी चीजें है जो हमारी कमियां हैं, उन पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, एमबीएज़ नहीं हैं, आज हमारे पास अधिकारी नहीं हैं - ऐसी चीजों के ऊपर हमें विचार करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपसभापति: सरदार तरलोचन सिंह। आपके पास 6 मिनट हैं।

सरदार तरलोचन सिंह (हरियाणा): धन्यवाद उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के भाषण पर हम सब धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कष्ट उठाया और वे यहां आयीं। लेकिन उनके भाषण में कई बातें जो बहुत जरूरी हैं, वह मैं इस समय यहां पर कहना चाहता हूं। पिछले साल जब राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया तो वन रैंक वन पेंशन आर्मी के लिए ऐलान किया था। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर रोज़ हम अखबार में पढ़ते हैं कि कश्मीर में वह कैप्टन मर गया, वे फौजी मर गए लेकिन यह सरकार आज तक, जो लाखों पेंशनर्स फौज के बैठे हैं, उनके लिए जो वायदा किया, उस वायदे को पूरा नहीं कर पायी और जो ऐलान आपने फौजियों के लिए किया, उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया।

क्योंकि उनकी मांग बिल्कुल clear[] है। जो जवान रिटायर होकर घर में बैठा है, उसकी पेंशन जो अब रिटायर होता है, उससे बहुत कम है। आप इतनी छोटी-सी बात फौजियों के लिए नहीं कर पाए और हर वक्त कहते हैं कि देश तैयार है, हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार है, अगर हमारा फौजी खुश नहीं है, फौजी हर गांवगा वं में यह कहता फिर रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला, तो हमारी समझ में नहीं आता है कि जो serving defence services में हैं, उनका क्या हाल होगा। सरकार ने उनको कहा था कि जो हम कमीशन बना रहे हैं, इसमें 1996 के पहले जो रिटायर हुए हैं, उनको भी वही हक मिलेगा, लेकिन अभी तक आपने नहीं दिया है। यह बहुत बड़ा इश्यु है। आप पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इसका हल निकालें क्योंकि पंजाब और हरियाणा दो स्टेट ऐसी हैं, जहां मैक्सिमम एक्स सोल्जर्स बैठे हैं। हमारे हर गांव में एक्स सर्विस मैन हैं। इसलिए उनको ध्यान में रखकर इस कार्य को किया जाए।

अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब कश्मीर गए थे और उन्होंने एक ऐलान किया है कि जो मिस गाइडिड यूथ कश्मीर से पाकिस्तान चले गए, हम उनको वापिस लेकर रिहेबिलेट करने के लिए तैयार हैं। मैं इसका वेलकम करता हूं। यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगर कश्मीर का मसला इस बात से हल होता हो, तो हम सब को वेलकम करना चाहिए।

डिप्टी चेयरमैन साहब, इसके साथ ही दो बातें बहुत जरूरी हैं। जब पाकिस्तान बना था, तो एक हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान में गया था, जो दो लाख लोग उस इलाके से कश्मीर में आए हैं, आज 61 साल हो गए, आपने उनको हिन्दुस्तान का शहरी नहीं माना।

श्री मोहम्मद शफ़ी (जम्मू और कश्मीर): सर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

†[شری محمد شفیع: سر، میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے۔]

श्री उपसभापति: इसमें आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री मोहम्मद शफ़ी सर, ये बात दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। उनको वही शहरी हुकूक हासिल हैं, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए लोगों को और यहां के लोगों को हासिल हैं।... (व्यवधान)..

†شری محمد شفیع: سر، یہ بات درست نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو وہی شہری حقوق حاصل ہیں، جو پاکستان ادھیکرت کشمیر سے آنے لوگوں کو اور یہاں کے لوگوں کو حاصل ہیں ---(مداخلت)---]

श्री उपसभापति: आपको भी बोलना है, आप उस वक्त बोलिएगा। ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं बनता है। ...(व्यवधान)...

सरदार तरलोचन सिंह: सर, आज भी जाकर जम्मू में देखिए, वे लोग कैसे मारे-मारे फिर रहे हैं और क्या मांगते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: शफ़ी साहब, जब आपका नम्बर आएगा, उस समय बोलिएगा। ...(व्यवधान)...

सरदार तरलोचन सिंह: मैं वही कह रहा हूं कि वे कश्मीरी हैं, वे हिन्दुस्तानी हैं। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए, उनको वही हक मिलें, जो हमारे शहरी को हैं। लेकिन जो हिन्दू सिख कश्मीर से कश्मीर में आए, उनको हक नहीं मिल रहा है, इससे बड़ा अन्याय भी कहीं होगा?

सर, दूसरी बात यह है कि जब आप कश्मीरियों को दे रहे हो, तो सिखों को देते वक्त क्या हो जाता है? जो हमारे लोग 25 वर्ष पहले मिस गाइडिड हो गए, जो चले गए, उनको बुलाना आपको याद ही नहीं रहता। क्या हम हिन्दुस्तानी नहीं हैं? क्या उन्होंने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? मेरी सलाह यह है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करो, तो उसको मजहब के नाम पर मत करो, सबको इनवाइट करो, जो मिस गाइडिड हैं, हिन्दुस्तान में बिलीव करते हैं, उन सबको बुलाओ।

सर, 25 साल पहले दरबार साहिब अमृतसर पर हमला हुआ था, दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ था, तो बहुत से सिख जो बाहर रहते हैं, उन्होंने जाकर डेमन्स्ट्रेशन किये इंडियन एम्बेसी के खिलाफ। आज 25 साल हो गए, उन लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट में पड़े हैं इंडिया उनको वीज़ा नहीं देता है। आज 25 साल हो गए, उनका कसूर सिर्फ यह है कि उन्होंने डेमन्स्ट्रेशन किया और आप इसलिए उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। हम उनके लिए वीज़ा मांगते हैं। हर सिख चाहे वह कहीं रहता है, वह रोज अरदास करता है कि मुझे अमृतसर जाकर दर्शन मिले, क्या आप यह छोटी सी बात भी करने के लिए तैयार नहीं हैं, इससे बड़ी डिसक्रिमिनेशन आपकी हमारे साथ और क्या होगी? मैं माइनारिटी कमीशन का चेयरमैन था। होम मिनिस्टर को हर जगह, हर रोज, सारे कांग्रेस एम0पी0 भी लिखकर देते हैं कि ब्लैक लिस्ट खत्म करो, हम भी कहते हैं। मैं तो यह भी कहता हूं कि आप एक कमेटी बनाओ, चाहे कांग्रेस के एम0पीज़ की ही बना दो, अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, वह इस ब्लैक लिस्ट को रिव्यु करे। अगर उनमें कोई ऐसा हो, जिसने कत्ल किया हो,

†[ ] Transliteration in Urdu Script.

डाका डाला हो, उसको न लाओ, लेकिन बाकी हजारों लोगों के नाम ब्लैक लिस्ट से काटे जाएं और उनको वीज़ा दिया जाए। हम तो वीज़ा मांगते हैं, rehabilitation नहीं। जो सिख बाहर बसा है, वह अपने गांव जाना चाहता है, वह दरबार अमृतसर में मत्था टेकना चाहता है, उसके लिए आप वीज़ा अलाऊ कर दो। अगर आपको शक है, तो उसके साथ पुलिस लगाओ, जब वह आएगा, तो वापिस जा सके। ऐसा करने से उसकी निगरानी भी रहेगी और आपको कोई ऐतराज भी नहीं होगा। ऐसा करने से आपको भी फायदा होगा, क्योंकि लाखों सिख, जो बाहर जा रहे हैं, वे आपका झंडा लेकर जाते हैं। अगर कोई सिख चलता है, तो लोग उसको इंडियन कहते हैं। आप उसको तो खुश रखो।

एक छोटी-सी बात और है। हमने फॉरेन मिनिस्टर साहब को सवाल लिखकर दिया, उसका आज जवाब मिला। मैंने इतना ही पूछा कि जो एनआरआई बाहर हैं, अगर उन एनआरआई़ज में मैक्सिमम पंजाबी हैं, तो कम से कम इंडियन ऐम्बेसी में एक पंजाबी Punjabi knowing officer ही लगा दो, लेकिन वह भी रिजेक्ट हो गया।

अब कनाडा में कनेडियन गवर्नमेंट ने पंजाबी लैंग्वेज को एडॉप्ट किया है । हमारी गवर्नमेंट कनेडियन एम्बेसी में पंजाबी आफिसर लगाने को तैयार नहीं है। ...**(व्यवधान)**... इस समय कनाडा में 6 लाख सिख रहते हैं और वहां पर हमारे हिन्दुस्तानी भाई 9 मैम्बर पार्लियामेंट हैं, फिर भी हम यहां पर एक पंजाबी आफिसर लगाने को तैयार नहीं हैं। सर, बहुत सी छोटी-छोटी बातें हैं,...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपके 6 मिनट हो गए हैं।

सरदार तरलोचन सिंह: सर, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा। भाइयो, हम हर साल लीडरों के लिए स्टेम्प जारी करते हैं। मैंने एक सवाल किया था, जिसमें बताया गया कि आज तक 56 स्टैम्प सैन्ट्रल मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स में जारी किए हैं, लेकिन उनमें सरदार स्वर्ण सिंह जी का नाम नहीं है। वे यहां पर 25 सालों तक मंत्री रहे हैं, फिर भी उनके नाम का स्टैम्प नहीं है। सरदार हुकम सिंह जी, पहले डिप्टी स्पीकर और फिर बाद में स्पीकर बने, उनके नाम का भी स्टेम्प नहीं है। सरदार गुरदयाल सिंह ढिलों के नाम का स्टेम्प नहीं है तथा सरदार बलदेव सिंह ने पं0 जवाहरलाल नेहरू के साथ लंदन जाकर इंडिया की आजादी के साइन किए थे और वे इंडिया के 6 साल कि डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके नाम का भी स्टेम्प नहीं है। इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन और क्या होगी। हम छोटी-छोटी बातों पर दरख्वास्त दें ...**(समय की घंटी)**... कि हमारे साथ यह किया जाए। सर, एक बात और है कि राजीव गांधी जी, जो एंटी डिफेक्शन दे गए हैं, इसमें लूपहोल्स हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उसका क्या हाल है? हरियाणा में एक पार्टी डिफेक्ट कर जाती है, लेकिन स्पीकर साहब यह करें कि जो डिफेक्शन लॉ में लूपहोल्स हैं, उनको बंद करो, या तो इसको विदड्रा करो या फिर इसको पूरी तरह से लागू करो। सर, एक डिस्क्रिमिनेशन की और बात कहता हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बस हो गया।

सरदार तरलोचन सिंह: सर, जितने कांग्रेस के लीडर हैं, चाहे वे कांग्रेस में हैं या नहीं हैं, उन सबका सम्मान हो। मैंने कई बार लिखा है, चौधरी देवीलाल यहां पर डिप्टी प्राइममिनिस्टर बने और वे अपनी जवानी में आजादी के लिए 6 साल तक जेल में रहे। हमने कहा कि वे जिस कोठी में रहे और जिस कोठी में उनकी डेथ हुई उनके ट्रस्ट के नाम पर उसको कर दिया जाए। बाकी सभी के नाम पर कर दिए हैं, लेकिन चौ. देवीलाल के नाम पर कोई करने को तैयार नहीं है। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो और क्या है? ...**(समय की घंटी)**... सर, आपने टाइम कम दिया है, लेकिन मेरी एक ही बेनती है कि यह मजबूत सरकार है और इसके पांच साल पूरे होंगे। अब यह दिन-ब-दिन मजबूती की ओर बढ़े तथा वोट बैंक व छोटी छोटी बातों से निकले। देश ने आपको यह मौका दिया है। ऐसी बातें करें कि सबका विश्वास प्राप्त हो तथा एक कंसेन्सस हो तथा सभी कार्य किए जाएं।

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise here to support the Motion moved by Prof. Kurien and supported by hon. Santosh Bagrodia. The

President's speech promises lower price and higher growth. Never before we have been so close as we are today to realize our national aspiration as dreamt by our founding father Mahatma Gandhi. Of course, in view of this globalization and the economic slowdown, the finance sector has collapsed in most of the developed countries like the US, Japan, Europe, etc. The GDP of a fast growing nation like China came to 13 from 8 point. So, India also came down to 6.7. The stimulus package provided by our Government has improved the condition to 7.5 and we are expecting growth in this year, that is, 2010-11 to be 8 per cent and we are also expecting to achieve growth of 9 per cent in 2011-12. I think this is a commendable job done by our Government, the Prime Minister and Finance Minister. The opposition should also appreciate the management done by the Government. The Government also promises to curb the price and everybody admits that there are many causes for food price rise. The shortfall of domestic production, impact of various schemes, salary rise, etc. are responsible for the upward movement of the price rise. But hoarding and middlemen are the main causes. We all also have to agree that although the Central Government should have the systematic plan and strategy to increase domestic production by strong action but the State Governments are really required to take action against the hoarders and the persons who are responsible for creating artificial scarcity and responsible for price rise. Sir, I want to mention here that this has been reflected here in the Budget also which has been placed here. If you look at the Budget, it has reflected the intention of the Presidential Address that 1,73,552 has been provided for infrastructure.

That is 46 per cent of the total Plan allocation and, also likewise if you look at NREGA programme, around Rs. 40 crores has been given and in social sector also 25 per cent of the total plan outlay has been given and Rs. 1,37674 crores has also been given for the social sector. That is 37 per cent of the Plan outlay. Sir, I want to mention this because the intention of the Government is to develop the infrastructure which will be helpful for building of our nation and also increase our GDP growth and on the other hand the Government has not overlooked the social sector also. Sir, I want to say, there were many discussions on NREGA programme also which has been named after our Father of the Nation, Mahatma Gandhi. This is a unique programme which is also being discussed and research work is being done in Harvard University, in Cambridge University and many other universities. What is this scheme and how can it be implemented in other countries? This is a very important scheme but the question is: we are talking about corruption in NREGA programme but who is implementing the NREGA programme? The Central Government is not implementing the NREGA programme. NREGA programme's management is with the State Government. It depends upon the State Government how they will implement in their respective States. If there is corruption, if there are any misgivings, then State Governments should be responsible. I think, if all State Governments will take initiative for the implementation of this programme this can change the face of our country in future also. I want to say and somebody has said in this House that some States

which have been supporting the minority community have been criticised in this House. Sir, I want to mention here that our Constitution itself says that our country is a secular, democratic country. We have to give protection, equal facilities to all the persons living here. We are also giving reservation to Scheduled Castes, Scheduled Tribes. They also belong to a particular religion. If the poor man of a minority community is also given reservation I think, there should not be any concern because everybody has got equal rights. I want to make it clear, Congress has given a principle. Neither build any temple nor break any temple; neither build any girja or masjid, nor break any girja or Masjid. कांग्रेस का काम मंदिर बनाना है, मंदिर तोड़ना नहीं है। कांग्रेस का काम देश बनाना है, जिनको मंदिर बनाना नहीं है, जिसको मस्जिद तोड़ना है, उनका काम वह कर सकता है। That is not the principle of the Congress to do that. Sir, I want to make it clear. Something was said about corruption.

An Anti-Corruption Convention was passed in 2002. Why has it not been ratified in this country? Sir, I want to make it clear that Government has never refused to ratify it. But we must also be thankful to the UPA Government who has brought the Right to Information Act. This Right to Information Act, I think, is the strongest arm to fight against corruption. Any Indian citizen can use in their respective work, in their respective district, in their respective State. What about the ratification of the Anti-Corruption Bill? That can also be discussed and there is enough time. Government can think and Government can also consider to ratify it. Sometimes we say that development is not up to the standard. Those who are saying that development is not up to the standard must not forget. This is a country where before 1947, where we had to depend on the gift of some countries for milk powder to feed our country's people, in our own country. But, after 62 years, here is a country where we have foodgrains to feed our people continuously for three years even if there is no production in our country. This is also the achievement of the Government whoever it is. It may be the Congress, it may be the BJP, it may be anybody else. It is very easy to say that there is no development. We may say that development is not up to our expectation. We may say that whatever money has been given has not reached the people. But saying that nothing has reached them is a negative approach. I think, it is not correct and it has been said by some of the people.

Sir, it has been stated in this House that during the Congress Government the difference between rich and poor has been increased. It is not a fact. Should we also analyze the six-year period when NDA Government was in power? What was the difference between rich and poor at that time? So, telling something and doing something is not good and does not make any sense. We must also realize and I fully agree with you that the difference between rich and poor should not be more. The Government should also make its policy framework to reduce the gap between rich and poor. But, in view of the situation that is prevailing worldwide/internationally and in an open market economy, it is very difficult to keep tab on that which we all understand very clearly.

Sir, if you look at the achievements of this Government, be it the Rajiv Gandhi Vidyutikaran Yojana or the Rural Water Supply Scheme or the Indira Awas Yojana or the Pradhan Mantri Sadak Yojana or the Golden Quadrilateral or the North-South-East-West Corridor, everywhere this Government has done a very good work and the same has been appreciated by one and all.

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

Sir, some hon. Members have mentioned about the schemes for SC/ST here. They have said that SC/ST people are living in this country. But, the Government has done nothing for them. I will be very happy if anybody or any political party come forward and give information that any Government — other than the Congress Government — has done more than what the Congress Government has done for SC/ST. Sir, whether it is reservation for SC/ST in Legislatures, Panchayats or scholarships or other benefits in education or reservation in employment, all this is done by the Congress Government. The Congress Government is equally concerned about the upliftment of Dalits and Advasis. I believe, our hon. Prime Minister and the UPA Government take appropriate steps to further redress the problems and grievances of the SC/ST.

Sir, I now come to women empowerment. Sir, now, this Government has decided to give 50 per cent reservation for women in Gram Panchayats and Zilla Parishads. The Bill is coming. Sir, the Government and our leader, Smt. Sonia Gandhi, are equally interested and have an agenda that the Women Reservation Bill will come before Parliament during the current Session. I believe, this will also get support from all the parties. I want to mention a point here. Sir, some people are making *halla-gulla* that OBC women should also get reservation. I wish to pose a simple question to them. If they are so sincere, they should be aware of the fact that there is no reservation for male OBCs. When the leaders were Chief Ministers in their respective States, they never tried to bring legislation for reservation of OBCs in Parliament or Assemblies. If there is no reservation in Parliament for male OBCs, how can you expect reservation for women OBCs in Parliament? So, it is nothing but preventing women to get their legitimate right which the UPA Government wants to give.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

This is only a political approach not to pass the Women Reservation Bill. And, Sir, I think, 50 per cent women in this country are taken care of by this Government through reservation...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, sit down...*(Interruptions)*...You are not speaking from your chair...*(Interruptions)*...Please sit down...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, this Government is determined to bring the Bill and women in this country would be given their due share. Sir, our President is a woman, our hon. Speaker is a woman and 33 per cent members in Assemblies and Parliament would also become women...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down...*(Interruptions)*...

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Sir, this credit goes to the UPA Government...*(Interruptions)*... This credit goes to the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh...*(Interruptions)*... Sir, this credit goes to our leader Smt. Sonia Gandhi who is the supreme leader in our country. I think, anybody can protest or anybody can say anything. But, truth and just will always prevail and nobody can prevent it. Sir, long-time has already been passed. The time has come and nobody should oppose it if they are really interested for empowering women.

Sir, I would like to dwell on one more point. This is regarding the agricultural workers because I myself come from this working class. In the Budget, rupees one thousand crores have been allocated for the social security of unorganised workers. I congratulate the Government that, at least, Rs. 1,000 crores have been allocated for this purpose. These workers are 400 millions in number. And, the Arjunkumar Sengupta Committee has recommended to allocate Rs. 22,000 crores for the agricultural workers alone. But this could not be implemented because of the shortage of money. I would like to request the hon. Prime Minister that when this is the issue of four hundred million workers, instead of one thousand crores of rupees, at least, twenty-thousand crores of rupees should be allocated for the social security of the unorganised sector workers.

The Government has taken a very good decision by extending the Rashtriya Swasthya Beema Yojana to all the 4.5 crores workers, who are working in the NREGA; and also by extending the Aam Aadmi Bima Yojana and the Rajiv Gandhi Swasthya Chikitsa Yojana to the ESI Corporation. I also congratulate the Government that the ESI Corporation is planning to have 27 medical colleges in the country. The Railways are also planning to have their own medical colleges. All these are very laudable schemes. The Railway Budget is also a very good Budget. I do believe that the UPA Government, under the leadership of Dr. Manmohan Singh, is going to do many more good works in this country. I also appeal all Opposition parties to support the UPA Programmes. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Barun Mukherji. You have six minutes.

DR. BARUN MUKHERJI (West Bengal): Sir, while supporting the Motion of Thanks on the President's Address, I would like to highlight a few points of my disagreement on the issue.

I am happy to note that the hon. President has expressed her heartfelt condolences for the victims of the terrorist acts in Pune. She has also expressed her concern on the Left Wing Extremists' violence in West Bengal; but, unfortunately, refrained from naming recent Maoist attack at Silda in the West Midnapore District of West Bengal, killing 24 EFR Jawans. It was reported in the media, immediately before the President's Address, that omission of 'condemnation of Maoists attack at Silda' was due to pressure on the Government from one of its allies. If that is the fact, the matter is really very unfortunate. Moreover, it is noted that the

hon. President has herself admitted that the Left Wing Extremism continues to be a significant cause of concern. The UPA Government has failed to contain the Ultra Left activities in the country. Also, it has failed to protect the poor tribal people.

Of late, the common people of our country are plagued with two most burning issues *viz.*, price rise and unemployment.

But these issues have not been adequately dealt with in her Address. And, also, no new hope is given to her countrymen. When she mentions about "unhappy pressure on the prices of foodgrains and food products", it appears that the gravity of unprecedented price-rise situation is underestimated and the solutions suggested are also neither convincing nor very effective. People were, therefore, disappointed when she expressed the Government's view that "higher prices were inevitable". In such a case, her assertion "that the Government continues to accord the highest importance to ensuring relief to the *aam aadmi* on food prices" is far from reality. Prices are steadily rising, with food articles' inflation almost touching 20.

The hon. President was perfectly right when she said, "our food security can be ensured only through sustained efforts at increasing agricultural productivity combined with a comprehensive reform of the Public Distribution System." Unfortunately, both the propositions made by her could not be fulfilled by the Government. Then the question comes: Is our food security at stake? The Government should answer it categorically.

As regards price rise, it should be noted further that prices of petrol and diesel have been hiked through Budged announcement, which, of course, came after President's speech. We wonder whether hon. President could have anticipated it, and, in that case, what could have been her reaction? But the fact remains. This hike in prices of petro products would further aggravate the already critical price-rise situation.

As far as the second burning issue of unemployment is concerned, the President's Address fails to convey to us any message regarding any new positive measures taken by the Government for increasing employment opportunities. The Government continues to harp only on its earlier NREGA measures, which has its own limitations, particularly, when in the new Budget for 2010-11, only a little increase in monetary provision has been made for it. Moreover, the Government continues to maintain its silence in case of urban employment guarantee for millions of growing unemployed youths in the urban sector. ***...(Time-bell rings)...*** We may now refer to a few other aspects of her speech. We do not find in hon. President's Address any positive assurance of early passage of Women Reservation Bill in the current Session of Parliament. It is regrettable that the Bill has been pending since May, 2008.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mukherjee, please conclude.

DR. BARUN MUKHERJI: It must be passed immediately. ***...(Time-bell rings)...*** The hon. President in her Address had tried to impress on us that there has been an increase in credit

flows and recruitment of minorities. But there was no mention of UPA Government's views about Rangnath Mishra Commission's report which has clearly recommended 15 per cent reservation for the minorities, and, particularly, 10 per cent for the Muslims. This omission is a great disappointment for the minorities. The UPA Government is boasting of the enactment of the right of children to free and compulsory education. ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

DR. BARUN MUKHERJI: Just one minute, Sir. But no budgetary provision has been made for necessary infrastructure, for proper implementation of the Act, particularly, for ensuring quality education. There may be free and compulsory education but how to ensure quality education. The hon. President's Address has failed to highlight it.

With these words of my reservation, Sir, I conclude my speech.

श्री मोहम्मद शफ़ी: जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, दो दिन से इस ऐवान में सदर के खुतबे पर बहस-ओ-मुबाहिसा हो रहा है। हिज्बे इक्तिदार में बजा-तो सदर के खुतबे में बयान की गई कामयाबियों का तफसील के साथ जिक्र है और हिज्बे इक्तिलाफ में अपनी रिवायत को कायम रखते हुए मुखालफत बराए मुखालफत को ही अपना उसूल बनाए रखा। हम भी तवक्को रखते थे, यह मुल्क जिन हालात से गुजरा, आलमी सतह पर एक माशी बोहरान था और उस बोहरान के असरात सारी दुनिया पर पड़े। हम यह तवक्को रखते थे कि हिज्बे इक्तिलाफ इस बात को कुबूल करेगा कि जनाब मनमोहन सिंह जी की कयादत में कायम सरकार ने इस आलमी बोहरान के असरात से मुल्क को बचाए रखा और तामीर-ओ-तरक्की के अमल को किसी तरह से भी इस आलमी बोहरान के असरात से महफूज़ रखा। यह कोई छोटी बात नहीं है। सारी दुनिया यह मानती है कि इतने बड़े आलमी बोहरान के बावजूद इस मुल्क की माशियत को बड़े ही तदब्बुर के साथ इस्तहकाम दिया और आज यह खुशखबरी हमें मिलती है, इस खुतबे सदारत में, कि आइंदा दो साल में हमारी तरक्की की रफ्तार दस फीसदी तक बढ़ेगी और जो रियायतें दी गई हैं, सरमाएदार तबका हो, उसको कह दीजिए या इंडस्ट्रियलिस्ट कह दीजिए, ताकि वे एक आलमी बोहरान के मनफ़ी असरात से महफूज रहें, उनको भी आहिस्ता-आहिस्ता वापिस लिया जाएगा।

मैं अपनी जमात जम्मू कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से यू0पी0ए0 की चेयरपरसन सोनिया जी को और वजीरे आज़म श्री मनमोहन सिंह जी को मुबारकबाद पेश करता हूं।

जो हम यह समझते थे कि खुतबे सदारत में दो-तीन गुज़ारिशात का जिक्र होना चाहिए था, उनके बारे में मैं दो-तीन गुज़ारिशात रखना चाहता हूं। वज़ीरे-आज़म ने चंद साल पहले रियासत जम्मू-कश्मीर में सियासी मामलात को हल करने के लिए एक गोलमेज कान्फ्रेंस बिठाई। उस गोलमेज कान्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ working groups बने और उन्होंने अपनी-अपनी रिपोर्टें मरकज़ी हुकूमत के सामने पेश कीं। उन रिपोर्टों की रोशनी में कई मामलात पर अमल हुआ, लेकिन हाल ही में जो बड़ी अहम रिपोर्ट Justice Saghir ने पेश की, रियासती हुकूमत के वज़ीरे-आला को पेश की और उन्होंने वह रिपोर्ट मरकज़ी हुकूमत को दी, क्योंकि वज़ीरे-आज़म के फैसले के मुताबिक यह कमेटी बनी थी। इस कमेटी में कुछ अहम सिफारिशात की गई थीं। कई तरह की आवाजें यहां पर सुनी जाती रहीं कि autonomy के नाम की कोई चीज बाकी मत रखिए। पहली बार इन सब बातों का जवाब Justice Saghir की रिपोर्ट में दिया गया और उन्होंने यह तस्लीम किया है कि इस रियासत को दफा 370 के तहत जो खुदमुख्तारी अंदरूनी तौर पर हासिल है, उसे न सिर्फ

बरकरार रखा जाना चाहिए, बल्कि इसमें जो erosion हुआ है, उस erosion को दूर करने के लिए ऐकदामात उठाने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि हमारे BJP के दोस्तों ने इस पर टिप्पणी की, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वाजपेयी जी, वज़ीरे-आज़म थे, उनके ज़माने में भी जब जेटली जी, वज़ीरे-कानून थे, उनके साथ भी इन मामलों पर बातचीत हुई। आज वे कैसे यह बात कहते हैं कि इस रिपोर्ट की रोशनी में कोई मुबाहिसा हो न गया हो ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: तब तो नैशनल कॉन्फरेंस NDA में था ...**(व्यवधान)**... आप यह बताइए कि नैशनल कॉन्फरेंस को क्यों ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद शफ़ी: हम क्या थे, क्या नहीं थे, यहां पर जेटली साहब तशरीफ फरमां हैं, ये उस कमेटी की सरबराही मरकज़ी हुकूमत की तरफ से कर रहे थे, उस वक्त हमारे सीनियर वज़ीर की सरबराही में जो कमेटी बनी थी, उसमें यह बातचीत हुई थी, महीयुद्दीन-शाह साहब की सरबराही में। हमने तब भी यह बात इनसे कही थी और आज भी इनसे इस ऐवान में यह बात कहना चाहते हैं कि आप बताइए कि इस कमेटी में जो रियासत जम्मू-कश्मीर की खुदमुख्तारी की बहाली की बात हुई, इसमें कौन सी ऐसी बात है, जिससे मुल्क की सलामती को खतरा हो सकता है या मुल्क के इस्तहकाम पर या इत्तिहाद पर कोई ज़र्ब लग सकती है? हमने तब भी इनसे यह बात कही थी, जेटली जी से यह बात कही थी ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: शफ़ी साहब, अब आप खत्म कीजिए, वक्त पूरा हो गया है।

श्री मोहम्मद शफ़ी: सर, दो-तीन मिनट दे दीजिए, कुछ अहम मुद्दे बाकी हैं।

श्री उपसभापति: आपको 6 मिनट का समय दिया गया था, आपने 8 मिनट ले लिए हैं।

श्री मोहम्मद शफ़ी: सर, मुझे दो-तीन बातें तो कहने दीजिए।

श्री उपसभापति: जब समय फिक्स हो जाता है, तो जो बोलना है ...**(व्यवधान)**...

श्री मोहम्मद शफ़ी: जनाब, आपने बड़ी दरियादिली दिखाई है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैंने किसी पर दरियादिली नहीं दिखाई है ...**(व्यवधान)**... आपको चाहिए कि आप समय के अंदर बोलें।

श्री **मोहम्मद शफ़ी**: आप मुझे दो-तीन मिनट और दे दीजिए। मेरी यह गुज़ारिश होगी कि वज़ीरे-आज़म जब इस मुबाहिसे का जवाब दें, तो वे जरूर इस बात का जिक्र करें कि ये जो Justice Saghir Committee की सिफारिशात हैं, इन पर वे क्या करने जा रहे हैं? दूसरी अहम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल यह बड़ा शोर मचा हुआ है कि बातचीत मत कीजिए।

बातचीत तो पहले भी अलेहदगी-पसंदी से जम्मू-कश्मीर में होती रही, जब एनडीए की सरकार भी थी। मेरी यह गुजारिश होगी कि यह जो बातचीत के अमल में आप कहते हैं कि नहीं, हम खामोशी से बातचीत करेंगे। खामोशी से तो कोई बातचीत होती नहीं है। जब आपने जिक्र किया कि हम खामोशी से बातचीत करने जा रहे हैं, खामोशी से क्या बात करनी है? टेबल पर बात कीजिए। बातचीत पहले भी होती रही है और अब भी होगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद शफ़ी: जो main stream parties हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, तब यह जस्टिस सगीर कमिटी की रिपोर्ट बनी है। अलेहदगी-पसंदी से भी बातचीत होनी चाहिए, ताकि इस सारे मसले का हल निकालने के लिए एक अच्छा माहौल बने।

श्री उपसभापति: ठीक है, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद शफ़ी मुझे एक बात और कहने दीजिए।

श्री उपसभापति: आप कितनी बात कहेंगे, कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद शफ़ी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दरम्यान "इंडस वाटर ट्रीटी" का बड़ा ही मुआहिदा हुआ। सारे मुल्क को उसका बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि हमें कुछ दरियाओं का फायदा मिला और उस पानी की वजह से हमने आबपाशी की स्कीमें भी बनाईं, बिजली की स्कीमें भी बनाइंर् और इससे मुल्क को फायदा हुआ। लेकिन इस "इंडस वाटर ट्रीटी" की रोशनी में जो हमारे दरिया, रियासत जम्मू-कश्मीर के दरियाओं से गुजरते हैं, (समय की घंटी) उनमें हम कोई पानी जमा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हमें हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Arjun Kumar Sengupta ...*(Interruptions)*...

श्री मोहम्मद शफ़ी मेरी यह गुजारिश होगी, हमारी riparian rights को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत को यह एक बड़ी grievance है ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह खड़े हो गए हैं, मैंने उनको बुला लिया है, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री मोहम्मद शफ़ी: उस पर तवज्जो देकर हमारे साथ यह जो नाइंसाफी हुई है, इसको compensate किया जाए। शुक्रिया।

†[**شری محمد شفیع (جموں و کشمیر)** : جناب ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہم دو دن سے اس ایوان میں صدر کے خطبے پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ حزب اقتدار میں بجاتو صدر کے خطبے میں بیان کی گئی کامیابیوں کا تفصیل کے ساتھہ ذکر ہے، حزب اختلاف نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے مخالف برائے مخالفت کو ہی اپنی اصول بنائے رکھا۔ ہم بھی توقع رکھتے تھے، یہ ملک جن حالات سے گزرا، عالمی سطح پر ایک معاشی بحران تھا اور بحران کے اثرات ساری دنیا پر پڑے۔ ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ حزب اختلاف اس بات کو قبول کرے گا کہ جناب منموہن سنگھہ جی کی قیادت میں قائم سرکار نے اس عالمی بحران کے اثرات سے ملک کو بچائے رکھا اور تعمیر و ترقی کے عمل کو کسی طرح سے بھی اس عالمی بحران کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ اتنے بڑے

†[ ]Transliteration in Urdu Script.

عالمی بحران کے باوجود اس ملک کی معیشت کو بڑے ہی تدبّر کے ساتھہ استحکام دیا اور آج یہ خوشخبری ہمیں ملتی ہے، اس خطبۂ صدارت میں، کہ آئندہ دو سال میں ہماری ترقی کی رفتار دس فیصد تک بڑھے گی اور جو رعایتیں دی گئی ہیں، سرمائے دار طبقہ ہو، اس کو کہہ دیجئے یا انڈسٹرئلسٹ کہہ دیجئے، تاکہ وہ ایک عالمی بحران کے منفی اثرات سے محفوظ رہیں، ان کو بھی آہستہ آہستہ واپس لیا جائے گا۔

میں اپنی جماعت، جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے یو۔پی۔اے۔ کی چیئرپرسن سونیا جی کو اور وزیر اعظم شری منموہن سنگھہ جی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو ہم یہ سمجھتے تھے کہ خطبۂ صدارت میں دو تین گزارشات کا ذکر ہونا چاہئے تھا، ان کے بارے میں، میں دو۔تین گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم نے چند سال پہلے ریاست جموں کشمیر میں سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لئے ایک گول میز کانفرنس بٹھائی۔ اس گول میز کانفرنس میں مختلف شعبوں کے لئے مختلف ورکنگ گروپس بنے اور انہوں نے اپنی اپنی رپورٹیں مرکزی حکومت کے سامنے پیش کیں۔ ان رپورٹوں کی روشنی میں کئی معاملات پر عمل ہوا، لیکن حال ہی میں جو بڑی اہم رپورٹ جسٹس صغیر نے پیش کی، ریاستی حکومت کے وزیر اعلی کو پیش کی اور انہوں نے وہ رپورٹ مرکزی حکومت کو دی، کیوں وزیر اعظم کے فیصلے کے مطابق یہ کمیٹی بنی تھی۔ اس کمیٹی میں کچھہ اہم سفارشات کی گئی تھیں۔ کئی طرح کی آوازیں یہاں پر سنی جاتی رہیں کہ autonomy کے نام کی کوئی چیزباقی مت رکھئے۔ پہلی بار ان سب باتوں کا جواب جسٹس صغیر کی رپورٹ میں دیا گیا اور انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس ریاست کا دفعہ 370 کے تحت جو خودمختاری اندرونی طور پر حاصل ہے، اسے نہ صرف برقرار رکھا جانا چاہئے، بلکہ اس میں جو erosion ہوا ہے، اس erosion کو دور کرنے کے لئے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے بی۔جے۔پی۔ کے دوستوں نے اس

پر ٹپّنی کی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب واجپئی جی وزیر اعظم تھے، ان کے زمانے میں بھی جب جیٹلی جی، وزیر قانون تھے، ان کے ساتھہ بھی ان معاملوں پر بات چیت ہوئی۔ آج وہ کیسے یہ بات کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی مباحثہ ہو نہ گیا ہو ...(مداخلت)...

شری رودرنارائن پانی : تب تو نیشنل کانفرنس این۔ڈی۔اے۔ میں تھا ...(مداخلت)... آپ یہ بتائیے کہ نیشنل کانفرنس کو کیوں ...(مداخلت)...

شری محمد شفیع : ہم کیا تھے، کیا نہیں تھے، یہاں پر جیٹلی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اس کمیٹی کی سربراہی مرکزی حکومت کی طرف سے کر رہے تھے، اس وقت ہمارے سینئر وزیر کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی، اس میں یہ بات چیت ہوئی تھی، محی الدین شاہ صاحب کی سربراہی میں۔ ہم نے تب بھی یہ بات ان سے کہی تھی اور آج بھی ان سے اس ایوان میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اس کمیٹی میں جو ریاست جموں کشمیر کی خودمختاری کی بحالی کی بات ہوئی، اس میں کون سی ایسی بات ہے، جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے یا ملک کے استحکام پر یا اتحاد پر کوئی ضرب لگ سکتی ہے؟ ہم نے تب بھی ان سے یہ بات کہی تھی، جیٹلی جی سے یہ بات کہی تھی ...(مداخلت)...

شری اپ سبھا پتی : شفیع صاحب، اب آپ ختم کیجئے۔

شری محمد شفیع : سر، دو تین منٹ دے دیجئے، کچھہ اہم مدّعے باقی ہیں۔

شری اپ سبھا پتی : آپ کو 6 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، آپ نے 8 منٹ لے لئے ہیں۔

شری محمد شفیع : سر، مجھے دو۔تین باتیں تو کہنے دیجئے۔

شری اپ سبھا پتی : جب وقت فکس ہو جاتا ہے، تو جو بولنا ہے ...(مداخلت)...

شری محمد شفیع : جناب، آپ نے بڑی دریادلی دکھائی ہے ...(مداخلت)...

شری اپ سبھا پتی : میں نے کسی پر دریا دلی نہیں دکھائی ہے ...(مداخلت)... آپ کو چاہئے کہ آپ وقت کے اندر بولیں۔

شری محمد شفیع : آپ مجھے دو۔تین منٹ اور دے دیجئے۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب جب اس مباحثے پر جواب دیں، تو وہ ضرور اس بات کا ذکر کریں کہ یہ جو جسٹس صغیر کمیٹی کی سفارشات ہیں، ان پر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دوسری اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ بات چیت مت کیجئے۔ بات چیت تو پہلے بھی علیحدگی پسندی سے جموں کشمیر میں ہوتی رہی، جب این۔ڈی۔اے۔ کی سرکار بھی تھی۔ میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو بات چیت کے عمل میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خاموشی سے بات چیت کریں گے۔ خاموشی سے تو کوئی بات چیت ہوتی نہیں ہے۔ جب آپ نے ذکر کیا کہ ہم خاموشی سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ خاموشی سے کیا بات کرنی ہے؟ ٹیبل پر بات کیجئے۔ بات چیت پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہوگی۔†

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude ...(Interruptions)...

شری محمد شفیع : جو main stream parties ہیں، ان سے بھی بات چیت ہونی ہے، تب یہ جسٹس صغیر کمیٹی کی رپورٹ بنی ہے۔ علیحدگی پسندی سے بھی بات چیت ہونی چاہئے، تاکہ اس سارے مسئلے کا حل نکالنے کے لئے ایک اچھا ماحول بنے۔

شری اپ سبھا پتی : ٹھیک ہے، اب آپ سماپت کیجئے۔

شری محمد شفیع : مجھے ایک بات اور کہنے دیجئے۔

شری اپ سبھا پتی : آپ کتنی بات کہیں گے، کرپیہ آپ سماپت کیجئے۔

شری محمد شفیع : ہندوستان اور پاکستان کے درمیان "انڈس واٹر ٹریٹی" کا بڑا ہی معاہدہ ہوا۔ سارے ملک کو اس کا بڑا فائدہ ہوا، کیوں کہ ہمیں کچھ دریاؤں کا فائدہ ملا اور ان پانی کی وجہ سے ہم نے آبپاشی کی اسکیمیں بھی بنائی، بجلی کی اسکیمیں بھی بنائی اور اس سے ملک کو فائدہ ہوا۔ لیکن اس

---

†[Transliteration in Urdu Script.]

"انڈس واٹر ٹریٹی" کی روشنی میں جو ہمارے دریا، ریاست جموں کشمیر کے دریاؤں سے گزرتے ہیں

....(وقت کی گھنٹی)....

ان میں ہم کوئی پانی جمع نہیں کر سکتے ہیں جس کے کارن ہمیں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے ---(مداخلت)--- †[ ]†

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Arjun Kumar Sengupta ...(Interruptions)..

شری محمد شفیع : میری یہ گزارش ہوگی، ہماری riparian rights کو مدّنظر رکھتے ہوئے مرکزی حکومت کو یہ ایک بڑی grievance ہے ---(مداخلت)----

شری اپ سبھا پتی : وہ کھڑے ہو گئے ہیں، میں نے ان کو بلا لیا ہے، کرپیہ آپ بیٹھہ جائیے۔

شری محمد شفیع : اس پر توجہ دے کر ہمارے ساتھہ یہ جو ناانصافی ہوئی ہے، اس کو compensate کیا جائے۔ شکریہ۔

†[(ختم شد)]†

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Arjun Kumar Sengupta ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to complete in six minutes. Reply is already delayed by ten minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: You have earlier told me ten minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to adhere to time.

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: I will try to complete within time. The point I want to put forward on the Motion of Thanks on President's Address is something which should be non-controversial and should be adopted unanimously. So, there is not much to talk about, to

† [ ]Transliteration in Urdu Script.

support and all that. But this gives us an opportunity to raise issues which are essential to the character and the nature of the Government and its programmes. Sir, as the President's Address points out, this Government has been elected to govern the country, for helping and redressing the grievances, welfare and improvement of *Aam* Aadmi, the common people. Sir, two years back a Commission, of which I happened to be the Chairman, identified what is this *Aam* Aadmi, who are these people we can call *Aam* Aadmi. There is a lot of misunderstanding on that Report and I am very happy yesterday Mr. Raja presented the main conclusions very correctly. In that Report, we did not talk about what is the poverty line, what should be the poverty line and anything of that kind. We accepted the poverty line given by the Planning Commission which is Rs. 12 per day per capita. But we divided the whole country in terms of per capita consumption. We did find that people below the poverty line have definitely come down between 1993 and 2004-05. But 77 per cent of the people are stuck at the level of consumption of Rs. 20. We did not say Rs. 20 should be the poverty line. We just got representation. But this is the distribution of population. What is very significant is that these Rs. 20 below people also contain most of our deprived people — the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the OBCs and the Muslim population.

Most of them are very poor. Most of them are also suffering from illiteracy, bad health, bad nutrition — all the things that are actually creating problems for everybody. That is the nature of our *aam* admi. There are 224 million people who are above them, who are doing very well. But, if you are concerned about rest of the 77 per cent, who are *aam* admi, we have to provide them some of the minimal things, like not only the right to food, but also health, education and livelihood. Most important point is that we have also found that the main problem of these people is that they do not have employment. Either they are unemployed or they are employed in the informal sector which does not have any job security, any income security and any kind of social security. So, this is the nature of our *aam admi*. That is all that we have pointed out in our report. And, I am very happy to point out that this report gave us the numbers only up to 2003-04 because that was the maximum period we could go to. Between that period and the current one, under the leadership of Dr. Manmohan Singh, this Government has done enormous amount of things, particularly because it has been able to raise the expenditure on social services programme much faster than any other Government could do. If you take a graph, you will find from 2003-04, the graph shoots up on the social expenditure. The result of that must be that the poverty has come down even further. I have no doubt about that.

Still, poverty is a big question. Even if the number of people, who are now consuming Rs. 20 per day, comes down from 77 per cent to 70 per cent, there will still be a large number of our *aam* admi who are deprived, who do not have proper livelihood. So, they have to be looked at. Sir, in this connection, I would submit to the Prime Minister — I am glad that he is here today —

that it is not just increasing the expenditure, he has to ensure that the expenditure is properly utilized, properly delivered. In the last year's Address of the President, there was a mention of an arm's length relation programme which will monitor, which will look into the way the things are done and ensure proper monitoring, proper social auditing and all that. This year's Budget document mentions that something of this nature will be created, but not outside the Government; it will be inside the Government. That is a little bit of a comedown because this particular thing should be outside the Government by independent people. Sir, this is the first point that I wanted to raise.

Secondly, the President's Address mentions about the prices. There is a statement there that if the oil prices are rising, it is inevitable that prices will also rise here. Sir, this is correct. I believe, in a modern world, where it is an open economy, we can't change the law of supply and demand. If the law of supply and demand creates a situation where the prices are going up, and if you try to interfere with it, it will only disturb the system. What we have to do, again from the point of view of *aam admi*, is to see whether we can contain the effects of price rise on *aam admi*. That is the point about which we should all be concerned. I am afraid my friends from the CPM do not appreciate this point because when I see that they are shouting, they are saying that petrol price increase is going to create a huge problem. It is going to create problem for whom? Of course, it will create problem for me, for Shri Sitaram Yechuryji, for Brindaji and others because we travel in cars and our expenditure will go up. But, this will not affect the *aam* admi. The only thing that will affect the *aam* admi*...(Interruptions)...* I have given you the definition of *aam admi,* which is below Rs. 20*...(interruptions)...* We are not a part of that. We must accept that.

MR. CHAIRMAN: Mr. Sengupta, you are running out of time. Please hurry up.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: We are not the poorest of the poor.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Will you yield for a minute? *...(interruptions)...* Even the tomatoes and potatoes are not consumed by them*...(interruptions)...*

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: No, let me complete. What I am saying here is if there is a price rise of diesel, it will affect many people.

SHRI SITARAM YECHURY: At least, roll that back.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Rolling back will not help*...(Interruptions)...* Would you listen to me please?

MR. CHAIRMAN: Please, you are running out of time.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: What I am saying is a hundred per cent increase in the diesel prices will affect the price of vegetables, price of onions, price of other things which are carried by trucks only by a very small .01 per cent.

That is what is going to affect the poor people. The point which I am trying to put forward to you is that you cannot protect everybody. You have to protect the *aam aadmi*, and, therefore, do not fritter away the energy on that kind of a situation.

Sir, let me come to my third point, which is very important point. Mr. Prime Minister has been able to explain the price increase in petroleum, and, the Budget will accept this. But the Kirit Parikh Committee Report asked for a more substantial increase. The Prime Minister must take the country into confidence, and, get its report implemented. It may be implemented by Shri Murli Deora in the Ministry of Petroleum. But the point which I am trying to say is that if you are talking about reforms, if you are trying about the economic fundamentals, the price of petroleum must be allowed to increase according to the report of the Kirit Parikh Committee. Sir, I come to my final point.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, it means, one more round is assured. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please make your final point.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, the final point is that the only way to protect...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, is it a pointer, a trial balloon?

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Sir, the final point is about the only way we can control the effects of the food prices increase on the common people. I spoke to Sharad Pawar ji and said that we can think of all kinds of long-term solutions but today's problem is today's problem. There is a huge increase in prices of foodgrains which is affecting the *aam* aadmi, and, what is the Government trying to do for that? It is very difficult to do much, but, at least, the Government should be able to convince the people that they are trying to do it, and, the only way to do that is to have a massive scale Public Distribution System for the poorest of the poor. This would mean increase in subsidies and that subsidy will have to be absorbed in the system. But there is something more important than that. I also heard Shri N.K. Singh pointing out, at the micro level, there is so much problem going on in the Public Distribution System; there are no shops, and, there are no proper methods of distribution, and, these things are creating problem on the ground, and, that has to be looked into.

Sir, I would submit that you might consider having a separate authority for Public Distribution System because here you have to bring in not only the Food Corporation but also NAFED and others who import pulses over a period of time, and, they should be considered together. ...*(Time-bell rings)*... One minute, Sir. I would like to speak on one more subject, which is very close to my heart, and, that is foreign relations, the Indo-Pak talks. I have been dealing with foreign policy...

MR. CHAIRMAN: Mr. Sengupta, I am afraid, you are running out of time.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Just one minute, Sir. I am quite appalled by this statement that talking to Pakistan is a great, you know, something, which is very much upsetting us. Why? We can talk to Pakistan on anything so long as we do not give in, and, only by talking, we can engage them. We cannot have the option of war; we cannot have the option of fighting Israeli kind of war in Pakistan. We do not have that. Sir, it is surprising to note that some of our very good friends, when they were in power, they did these things but now they think that any kind of talk is something under pressure of the United States. I don't see any change in our Government's policy because of any pressure of the United States. So, I wanted to make this particular point clear, which has something which is connected with the President's Speech, connected with our general future, and, it should be noticed, Sir. Thank you very much.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, hon. Prime Minister.

THE PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, I rise to join all Members of this august House in conveying our sincere thanks to the hon. President of India for her enlightened Address. For the past two days, we have had a very constructive debate on the issues covered in Rashtrapati ji's Address. While several Members have expressed satisfaction at the working of the Governments, others have criticized it. This is as it should. Mr. Chairman, Sir, I have listened with great respect yesterday to Mr. Venkaiah Naidu and also to Mr. Yechury. I was not present here all the time but I have taken note of various points which have been expressed in this august House and I will try to respond to the main points which emerged from this debate. Let me say that I listened with great regard and respect to my old friend and colleague, Arjun Kumar Sengupta, and his is a voice of sanity which, I think, I greatly endorse.

Mr. Chairman, Sir, yesterday, while initiating the debate, Shri Venkaiah Naidu asked what are the challenges and how are we going to face those challenges. I think, that question was answered by Shri Yechury very well when he quoted from the last paragraph of the Rashtrapatiji's Address in which she quoted Jawaharlal Nehru's famous statement on the midnight of 14th August 1947 and if we identify the challenge, the challenge is, the service of India. What is the meaning of the service of India? It means the service of the millions who suffer; it means ending poverty, ignorance and disease and inequality of opportunity. That challenge has remained with us. Poverty, ignorance and disease and their eradication is the most important challenge before our country and before our polity. A lot has been done to soften the harsh edges of extreme poverty. But much remains to be done. Therefore, it is our collective responsibility to reflect as to how best we can get rid of this massive burden of crying poverty, ignorance and disease which still afflict millions and millions of people in our country. There are differences about measuring poverty, and I am not going into that. It is the general consensus that during the first three decades of our independence, despite major achievements, the

proportion of people below the poverty line declined very little. Since then, there has been a decline though people differ as to the precise number of people who are below the poverty line. I accept that the people below the poverty line are our primary concerns and, therefore, the identification problem is important but it is only the beginning of finding a solution.

Therefore, the effort must be how we can ensure that the poor are brought into the mainstream of the national scheme of things. The more I reflect on this, the more I am convinced that the only way in which we can find meaningful solutions to the problems of mass poverty is through a rapidlyexpanding economy. If our economy is not expanding, the problems of re-distribution, even if you can manage them, become formidable obstacles to national cohesion, because if the economy is not growing and you want to re-distribute the income or wealth, then, the process becomes a zero-sum game and if the process of re-distribution becomes a zero-sum game, it will arouse resistance, some time successful, some time unsuccessful. But in a parliamentary democracy, wedded to peaceful means of resolving social conflicts, I think, this will be a bit tragic.

However, if the economy is growing at a rapid rate, you can redistribute also without too much social tensions, because in the process of redistribution what people lose, in an expanding economy, is not an absolute loss, but a relative loss. Therefore, I do submit that for the management of a polity as diverse, as complex, as India's is, unless and until our economy is growing fast enough, we will not be able to deal with the problems of poverty. This is not to say that growth is an end in itself; growth is only a means to an end. We can help some people, who are poor, through social security measures. But there are limitations, and these limitations are all the more severe if the economy is not growing. But if the economy is growing and we marry it with an employment intensive pattern of development, you lift people above the poverty line much more effectively than through other means of public services important though that means may also be. Therefore, if you want more growth, we have to work for it. Antigrowth rhetoric has no substance; it has no meaning. All that we can say is that growth must be accompanied by a social commitment, to see that this is inclusive. This is a process which will lift the millions and millions who are at the lowest rung of the ladder. Therefore, along with growth, we need strategies for employment generation; we need strategy for social empowerment through education, through health. We need to go for social security measures, for the truly deprived and backward, of the type which we have been trying to attempt in recent years. They need to be implemented much more vigorously, much more effectively. I will be the last one I think to deny that.

I would say that India faces enormous challenges. But we are also on the cusp of great opportunities. Ten years ago, if you had asked me whether India would be able to have a savings rate of 35 per cent or an investment rate of 37 per cent, everybody would have laughed it away.

But structural changes have come about in this economy. Today, we have savings at 35 per cent of our GDP, and our investment rates are 37 per cent of our GDP. These are the miracle rates of savings and investments which one used to associate hitherto only with the East Asian or South East Asian countries, including China. We are, I think, therefore, on the verge of that opportunity where, with this rate of investment of 35 or 36 or 37 per cent, with a capital output ratio of 4:1, a growth rate of 9-10 per cent is eminently obtainable.

I submit to this august House that on the challenge of mass poverty, let us work together, convert it into an opportunity for building an India free from the fear of war, want, and exploitation.

It is in this context that I look at the achievements of the last four or five years. Not that we have solved all the problems, but the fact is that until the beginning of the global economic crisis of September 2008, in the previous three years, the economy had grown at the rate of over nine per cent per annum.

It's a remarkable development. In the face of an acute global crisis which led to negative rate of growth in countries as advanced as the United States, as advanced as countries of the European Union, India still was able to sustain in 2008-09, a growth rate of 6.7 per cent, rising to a growth rate of, at least, 7.2 per cent and hopefully, 7.5 per cent this year, which is an achievement. And, I am confident, if we manage our affairs well and if we deal with the social tensions that bedevil our polity well, we are in the realm of a double-digit growth era. If that comes about, if by the year 2011-12 we return to the growth path of nine per cent per annum and if in addition, we take note of the demographic changes which are taking place, I think, you must recognise that our working labour force as a proportion of the total work force is going to rise sharply in the next two decades. Everywhere that process of demographic change has been associated with a sharp increase in the savings rate. So, I am confident, if we manage this process well, the savings rate in India would rise to 40 per cent or more. And with that, we can look forward to an era of double-digit growth, perhaps the fastest growing economy of the world. That is something which is within reach. If we manage our affairs well, if we ensure that along with the raising of savings and investment rates, we manage our social and economic infrastructure well and if our processes of governance are reformed so as to minimise the scope for corruption, so as to minimise the transaction cost of doing business in our country, I think, great opportunities are now on the horizon. And, whatever be our differences, I think, Jawahar Lal Nehru's dictum that the service of India means the service of the poor and the millions who suffer, should unite this House so that the Government and the Opposition of all shades of opinion working together can push the growth process in a manner that it will become the servant of social change. That is the approach our Government has adopted for the management of the economic and social policies. It will be far too presumptuous on my part to

say that there are no pitfalls, that there are no leakages. I do recognise that. It is in that spirit, that I take the criticism that emanates from the Opposition Benches or from the Treasury Benches. I think, that's a healthy part of the functioning of Parliamentary democracy. I welcome this opportunity given to me to respond to some of the specific issues which have been raised in the course of the debate.

The first and the foremost issue that concerns the Members on this side as well as on that side is the issue of food inflation. I do recognise, food inflation is a major problem and that every effort should be made to bring it down to lower, normal levels. But, I would like the House to appreciate that until 2007, things were moving broadly in the right direction. Then, in the first half of 2008, there was a sharp upsurge in international commodity prices and whether we like it or not, we are today integrated in the world economy, in a manner, which was not the case some 10 or 20 years ago.

We are dependent on petroleum products to the extent of 70 per cent of our imports, we are dependent on fertilizer supplies to a very substantial part of our requirement, we are dependent on vegetable oils and oil seeds for a substantial part, we are dependent on pulses the production of which is stagnant at 14, 15 million tons for a decade, and we are dependent in times of shortage of sugar on imports. And when we talk of sugar, I think, any text book on Indian Economics will tell you that there is a 2 to 3 years cycle in the operations of the sugarcane economy of our country. There are two or three years when prices go up. That induces farmers then to switch more the area under sugarcane cultivation that leads to a glut that lost another 2 or 3 years. So, this cycle has prevailed, and if there is a failure of the economic policy, it is with regard to the management of the sugar economy. It is this that when a cycle does exit, we have not been able to find practical, pragmatic means of dealing with this cyclical behaviour without too much pressure on prices. That I do admit is a weakness. But I think that is a weakness which is basically the result of the nature of the cyclical pattern of sugarcane production, I exhibited for the last 50 or 60 years that I know of even before Independence times. Therefore, in the background of steep rise in imported prices, some pressure on domestic prices was inevitable. And then comes the drought, associated with the failure of the south-west monsoons that compounded the problem on the price front. There was a steep fall in the production of kharif rice; there was a steep fall in the production of pulses in the kharif season; there was a steep fall in the production of sugarcane. These are the 3 or 4 commodities which dominate the food recession, and if you did not have this phenomenon of drought, followed by floods in Andhra Pradesh, floods in Karnataka, I think the situation might have been different. But these were circumstances beyond the Government's control. That food price rise did cause worries, that it brought hardships to the poorer sections of the community, it is undeniable. But I think this was the situation where there was very little option for the Government except to cushion the

poor to the extent it could against the rise in prices, and I take some credit for this Government that since 2002, there has been no increase in the prices of Public Distribution supplies to below the poverty line people as well as to that category which is technically characterised as above the poverty line. So, the Public Distribution System in this country may be mismatched, but we distribute annually through the Public Distribution System about 40 million tons of foodgrains, mostly rice and wheat, meant for the poorer sections of our population. The total production of foodgrains in the best of times has been about up to 33 million tons. So, 14 million tons available for Public Distribution to the poorer sections of the society... if the system is well managed, is a powerful source of intervention and the challenge is not, I think, to say that the Public Distribution System should be dismantled, but that the Public Distribution System should be so strengthened that it can really reach out to the poor is the challenge. A large number of bogus cards that exist in all States of the Union, I think, become a thing of the past. That traders who supply foodgrains do not mismanage, this is the challenge before the Centre, before the States. Ultimately, it is the responsibility of the State Government to mange the Public Distribution System. But I do submit to you, Sir, that the responsibility of the Central Government to provide about 40 million tonnes of foodgrains at fixed prices, which have not been changed since 2002, is an act which, I think, needs some appreciation even if you are in the Opposition. This is the background of the inflationary rise. But I do agree that inflation is a concern which cannot be wished away.

The question is: how do you deal with the inflation? If inflation was the only concern, I think, I could have instructed the Reserve Bank to control the money supply expansion in a manner that inflationary expectations would have been do used. That was an option. But if we had done that, and the way the world was facing a global recession, the problem of unemployment, a large scale unemployment, in India, would have become a mass problem. In fact, as I said, the whole world was experiencing a recession, but our country still managed to stay afloat though with reduced growth rates. The figures that have been given of employment in our country, the behaviour of employment, there are no compilation of statistics of employment generation of all sectors. The Economic Survey of this year has used its data, a sample survey data, to take a look at the employment situation and it emerges that whatever may have happened in the world outside, the unemployment situation in India was not allowed to be aggravated as a result of the measures that we had adopted as fiscal stimuli. If we had used the harsher monetary policy, that would have hurt more people than it has done today. It would have caused more worry to the poor, to the people, to those who would have become unemployed. So, if you have a choice to make inflation or unemployment, I submit that if you can curb the effects of inflation through the Public Distribution System, the employment aspect can best be dealt with in the manner in which our Government dealt with it through a fiscal stimulus. Any other course, tightening of our fiscal and monetary policies would have hurt the poor a lot more. And this is the explanation that

I have to offer to this House when you review the inflation, the factors behind it, and the consequences of it. But having said that, I do agree that in the months to come, we should, I think, look at more effective means to curb the inflation. Fortunately, the *rabi* crop prospects are quite good; prices of some commodities have also started declining. My own feeling is that the worst is over. That is what I said to the Conference of Chief Ministers. I stand, I think, by that statement.

Mr. Chairman, there has been some discussion on the export of sugar. I think, Shri Venkaiah Naidu has talked of a scam. Now, I think, the Opposition smells a scam everywhere. I can't help it. But the plain facts are as I will describe in a moment.

The first thing I do wish to point out is that when you are in an international trading environment, you have to honour the international commitments. If you don't honour your commitments, I think, next time you may not be able to retain that market. This was the case. The amount of sugar that India has exported has to be viewed in relation to imports, and in relation to imports the exports that we made to honour the contractual commitments are so small that it is surprising that so much is being made of these exports. In November, 2009, India exported sugar worth Rs. 7.94 crores, whereas it imported sugar worth Rs. 611.40 crores. In December, 2009, the exports of sugar were worth Rs. 12.34 crores, whereas the imports were worth Rs. 216.90 crores. Therefore, I think, the conclusion to which I am led is that even if you were able to prevent these small exports, they would have made very little difference to the price situation. In any case, the imports far exceeded the exports.

Mr. Chairman, Sir, an economy, with all its potential, does not grow in isolation. I would say that the economy does not grow in a vacuum.

Rightly, several Members have made a reference to the internal security situation in our country. There is no doubt that terrorism and naxalism are causes of serious concern. Our country has to grapple with these menaces and can grapple with it with all its force and with all its might. That is the assurance that I wish to give to this House and this is an area where there will be zero tolerance for terrorism or for naxalism or for such other things. I would also say that in dealing with naxalism we are dealing with our own people. These are some of the misguided people. If they abjure the path of violence, if they give up this approach to solving the problems, we are willing to talk to anyone who has any concrete, constructive solution to deal with the problems of the Tribal belt, which, I do agree, has not received the attention thus far of development planners to the extent that it should have.

I was saying that we are taking firm action to curb naxalite violence. It is unfortunate that the naxalites are targeting the innocent people and destroying roads, power-lines and other essential infrastructure. In some places we have received reports of the use of children. A high-level meeting was recently held with all the Chief Ministers where we reviewed the entire situation. We have drawn up an integrated action plan to tackle the naxalite problem in

consultation with the States. The security forces have achieved several notable successes of late.

While, as I said, we are determined to take firm action, we are ready to talk to any group that abjures violence unconditionally and agrees to abide by the due constitutional process.

Sir, as regards terrorism, the National Investigation Agency has commenced its work. Four Regional Hubs of National Security Guards have been set up. We are in the process of setting up a National Counter Terrorism Centre. A National Committee on Coastal Security has been set up which has adopted an integrated approach to coastal security and has taken major initiatives and decisions for registration of vessels, issue of identity cards to fishermen, installation of transponders on boats and setting up of four Joint Operation Centres. Coastal Police Stations and interceptor boats have become operational under the coastal security scheme. To supplement the efforts of the State Governments in modernising their police forces, we have provided Rs. 1,250 crores during the current year, of which Rs. 955.53 crores have been released to States up to 28th January this year. This has helped States in augmenting the resources available to police forces in terms of vehicles, weaponry, communication, training, forensic facilities, intelligence capabilities, security equipment and buildings. The Bureau of Police Research and Development is engaged in an in-depth assessment study of the scheme so that the scheme could be improved upon.

Yesterday, Shri Naidu and also some other Members referred to the agricultural situation in our country and the neglect of agriculture. It is certainly true that agricultural output in the current year, according to the latest estimates of the CSO, will show a decline of 0.2 per cent. But looking at the background of the developments in the current year, the effect of a bad monsoon followed by drought, I think, this is a measure of the success of Indian agriculture that even a severe drought, the worst since 1972, has brought about a decline of only 0.2 per cent in agricultural output during the current fiscal year.

A drought, after all, is beyond anybody's control. A severe drought does result in negative growth in agriculture and it is no surprise that agriculture is expected to grow at -0.2 per cent in 2009-10. We should not, however, forget that in 2002-03, following the drought of 2002, agricultural growth went down by a good 7 per cent; food production went down from 202 million tonnes in 1998-99 to 174 million tonnes in 2002-03. I would also like to humbly remind the Members that the agricultural sector has been growing at an average rate of 4 per cent during the period 2005 to 2008, compared to the growth rate of around 2 per cent from 1997 to 2002. Our pro-farmer policies have borne fruits. For the first time in the recent past — the figures are there in the Economic Survey — we have reversed the longterm trend of decline in investment in agriculture and stepped up investment in agriculture through the Accelerated Irrigation Benefit

Programme, the Rashtriya Krishi Vikas Yojana, the National Food Security Mission, the National Horticultural Mission and other such schemes. We should also not forget the investment in water conservation structures that is being made through millions of works under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

Food production had increased from 174 million tonnes in 2002-03 to 233 million tonnes in 2008-09, which represents a growth rate of around six per cent per year. But I am conscious that a lot more needs to be done to improve agricultural productivity, and we are committed to continuing our efforts to increase both public and private investment in agriculture and to diversify agriculture so that higher farm incomes provide stability to the lives of millions of our farmers. The decision to pay remunerative prices by way of increased Minimum Support Prices is a part of our effort to incentives growth of agricultural production and productivity. I should also say that one of the weaknesses of the agricultural system in our country is the decline in the effectiveness of agricultural extension services in a large number of States. I think that is weakness which has to be plugged. The State Governments have to be mobilised to go back to the old system of extension under which India began the Green Revolution. In ushering in of the Green Revolution, the extension services in our States played a very important role. But, in many States, I think, the extension machinery has become very lethargic. Unless it is activated I think, we will be talking in the air when we are talking of increasing agricultural productivity or agricultural production.

I think it was Shri Naidu who raised the issue of rights of tribals over forests. We are making all possible efforts together with the State Governments to ensure early disposal of claims and distribution of titles under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act. I have also requested the Chief Ministers of concerned States, on three occasions, to take all possible measures necessary to accelerate the process of implementation of the Act and ensure expeditious distribution of title deeds to all eligible claimants. It was reiterated through the Conference of Chief Ministers and State Ministers, held in November, 2009, to review implementation of the Act. The Ministry of Tribal Affairs is closely monitoring the progress in this regard.

I think it was Shri Ram Gopal Yadav who expressed concern over the implementation of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Let me say that this is a scheme which has the potential to change the phase of rural India. To increase its impact, we have initiated measures to bring in greater transparency and accountability. An ombudsman scheme for setting up an independent Grievance Redressal Mechanism at the district level has been formulated, and States are in the process of setting up District Ombudsman. Social audits by Gram Sabhas have also been taken up. Details of job cards, master roll and works undertaken have also been placed in the public domain. The scheme for an independent

monitoring by eminent citizens has been formulated. Efforts will continue to be made to improve the implementation of this scheme.

Mr. Chairman, Sir, Shri Naidu brought out the issue of the State of Telangana and I would, therefore, like to state the position as I see it. The issue of statehood to Telangana has been raised by some hon. Members. Please allow me to say that it was only after considering the minutes of the meeting of the floor leaders of political parties in the State Legislature called by the Chief Minister of Andhra Pradesh that the Central Government announced its decision to initiate the process of forming the State of Telangana. It was also announced that an appropriate resolution would be moved in the State Assembly. However, in view of the subsequent developments in Andhra Pradesh, we are of the view that the matter requires wide-ranging consultation with the aim of forging a consensus amongst all concerned. A committee has been set up under the chairmanship of Justice B.M. Srikrishna to take things forward. The committee is expected to consult all sections of the people, especially the political parties, on the aforesaid matter and elicit their views to seek from the political parties and other organisations a range of solutions that would resolve the present difficult situation and promote the welfare of all sections of the people to identify optimal solution for this purpose and to recommend a plan of action and a roadmap. It is also expected to consult other organisations such as industry, trade unions, farmers organisations, women's organisations and students organisations on the aforesaid matter and elicit their views with specific reference to the all round development of the different regions of the State and give a report by December 31, 2010.

Mr. Chairman, Sir, I think it was Mr. Naidu who referred to the creation of the three States when his Party was in power at the Centre. That is correct. But those were the cases where there was no difference of opinion between all the stakeholders. It was easy to take that decision. But, in the present situation, I think things have worked out differently and I, therefore, appeal to the Members to bear this in mind.

Shri Naidu referred to the issue of black money. I would like to inform the House of the steps we have taken on this matter. Twenty countries and jurisdictions have been prioritised for entering into agreements regarding exchange of information and assistance in the collection of taxes. Negotiations have been completed with the Bahamas and Bermuda and steps are being taken for signing of agreements. We have also approached Switzerland for renegotiation of our tax treaty, so that we can have access to bank information. Negotiations were held in November, 2009 and the matter is being pursued for finalising a new protocol through which we will be able to obtain information in specific cases. India is an active participant in global fora for improving transparency and exchange of information on tax matters.

Mr. Chairman Sir, Shri Yechury raised the issue of one rank-one pension to the ex-servicemen. The factual position in this regard is that we had constituted a committee under

the Cabinet Secretary to look into the issue of one rank-one pension and other related matters. The Committee did not recommend one rank-one pension but whatever recommendations the Committee made to substantially enhance the pensionary benefits of personnel below officer rank and of commissioned officers were accepted by the Government, and this is what I had stated in my Independence Day speech. The recommendations which have been accepted cover what the Finance Minister had promised in his Budget Speech of 2009. Of the seven recommendations that the Committee made, five have been implemented. The two recommendations which have not been implemented will be implemented very soon.

Mr. Chairman, Sir, with regard to the Women's Reservation Bill, we introduced the Women's Reservation Bill in the Rajya Sabha in May, 2008. We have already considered the Report of the Standing Committee of Parliament on this Bill. It will be our endeavour to bring the Bill before Parliament in this very Session. I sincerely hope that hon. Members will support the Bill as it would be the strongest affirmation of our commitment to the empowerment of our women.

Mr. Chairman, Sir, I should say a few words about Foreign Policy. The Government's Foreign Policy has been based on national consensus and full adherence to the principles and objectives laid down by the founding fathers of our Republic. The Foreign Policy that we pursued in the first term of our Government, around which we have built upon in the second term, has yielded solid results. India's standing in the comity of nations has never been higher! In the troubled world that we live in, there is respect for India's role as a force of moderation, reason and stability. The resilience of our democracy, our commitment to pluralism and secularism and the strength of our economy have greatly enhanced our standing in the world.

Sir, several Members have voiced their concerns over the situation in Pakistan and the terrorism that is emanating from there against India. The Government fully shares these concerns. We are taking all necessary steps to strengthen our internal security and defence capability. The Government has kept Parliament fully informed at every stage of our policy towards Pakistan. I had made a detailed statement on our approach towards Pakistan in this august House on 29th July, 2009. The External Affairs Minister briefed the House on the last round of Foreign Secretary level talks in February. Our policy towards Pakistan is consistent, cautious and realistic. I have never believed that the channels of communication with Pakistan should break down. Even at the height of the Cold War, the Americans and the Soviets used to speak to each other. The chances of mis-calculation can only increase in an environment of 'no contact.' I, therefore, personally conveyed our concerns to President Zardari when I met him in Russia and later to Prime Minister Gilani at the NAM Summit last year. I had made an offer of talks on humanitarian and other issues in October last year during my visit to Anantnag. The decision to resume talks at the Foreign Secretary level is not a sudden decision but a calculated

one, based on weighing all the costs and benefits. The fact of the matter is that the rest of the international community, despite Pakistan's role in terrorism, is talking to Pakistan. So, our not talking to them is not going to isolate them. We have made our points strongly, but we cannot wish away the problem by not talking to them. Dialogue is the only way forward for civilised countries to resolve their problem. But, it is equally true that for any meaningful dialogue to proceed the terror machine has to be controlled by Pakistan even if non-State actors are at work. I have had many discussions in this regard. Pakistan must fulfil its assurances that it will not permit any territory under its control to be used to support terrorism in any manner directed against India. I have said so in Parliament a number of times and that remains our consistent position.

Some hon. Members — I think, it was Mr. Yadav — have referred to my discussions in Saudi Arabia on Pakistan. Saudi Arabia is also affected by terrorism and this was one of the subjects that came up in our discussions.

I discussed India-Pakistan ties in this context. I mentioned to the Saudi leadership as I had to other world leaders as well that all problems between India and Pakistan can be resolved through meaningful, bilateral dialogue if only Pakistan were to take a reasonable attitude in dealing with those terrorist elements who target our country. I wish to reaffirm that no offer was made seeking mediation. We do not need any mediation. We are talking directly to Pakistan.

Some Members have said, I think, Mr. Naidu hinted, that we acted under U.S. pressure. I think, we do a disservice to any Government and Prime Minister of this proud country if we say that such fundamental matters of national security and foreign policy were decided based on anything but our supreme national interest.

I have had by now many discussions with President Obama since he took office. I categorically state that not once has he sought to pressurize India into taking one position or the other. On the contrary, he has always expressed understanding of the positions we have taken from time to time. I would urge the Opposition not to spread disinformation on sensitive aspect of our foreign policy.

Mr. Chairman, Sir, let me say that we do not wish to see the involvement of foreign powers in the affairs of South Asia. Whatever our problems, we must learn to talk to each other and resolve our problems in a peaceful manner using our own creative genius. In Afghanistan, our assistance has received widespread support among the people of Afghanistan. The entire nation was outraged by the most recent brutal attack in Kabul on February 26, which led to the loss of seven innocent Indian lives. These Indian nationals were in Afghanistan on a mission of peace, of goodwill and friendship helping to construct the peaceful and democratic Afghanistan that our Afghan friends desire. We condemn this dastardly act. I wish to assure this House that such attacks will not bend the will of the people of India.

Sir, Mr. Naidu also brought in the issue of India China relationship and I should like to state that China is our neighbour with whom we have a comprehensive and multi-sectoral

relationship. We wish to build upon the achievements so far to create a partnership that is mutually beneficial. We are convinced that good relations with China are in the interest of both countries and will contribute to peace, security and stability not only of the Asia Pacific region, but also of the world. We are both committed at the highest level to maintain peace and tranquility on the border, pending the resolution of the border question. This is a complex matter which will take time to resolve. I had an excellent interaction with Prime Minister Wen Jiabao in Copenhagen, and our cooperation in the area of climate change is a shining example of how our two countries can work together on issues of global importance and those which impinge on the future of our two peoples.

Some Members raised the Tamil issue in Sri Lanka. The conclusion of military operations against the LTTE has opened opportunities for finding a lasting political settlement acceptable to all communities, particularly the Tamil community, with a united Sri Lanka. We have and we will continue to contribute to the humanitarian and rehabilitation efforts of the Sri Lankan Government and to the long-term reconstruction of areas that have been affected by the military conflict.

Our assistance package of Rs. 500 crores for immediate relief, resettlement and reconstruction is under implementation. Mr. Chairman, Sir, our country is passing through a difficult phase. Security and stability are the need of the hour. Political parties can differ on various issues but I do believe it is important for us to face challenges in a united manner. I seek the cooperation and support of all sections of this august House. Let us not allow narrow partisan considerations to come in the way of effective governance of this great country. The people of India expect both the Treasury and Opposition Benches to engage constructively and work together for the safety, security and prosperity of our citizens. I thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: I thank you, Mr. Prime Minister. I shall now put the amendments to vote.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 1 to 36 and 334 to 348 are by Shri Moinul Hassan. He is not present.

Amendment Nos. 1 to 36 and 334 to 348 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 37 to 81 by Shrimati Maya Singh. Are you withdrawing your amendments or do you want them to be put to vote?

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): सर, मेरे द्वारा जो संशोधन रखे गए हैं, वे अपने आप में गलत नहीं हैं, लेकिन सरकार के आश्वासन में जो बातें कही गई हैं, उनको देखते हुए कि सरकार उनको हल करने के लिए गंभीरता से विचार करेगी, मैं अपने अमेंडमेंट्स वापिस लेती हूं।

Amendments (Nos. 37 to 81), were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 82 to 103 and Amendment No. 612 by Shrimati Brinda Karat. She is not present.

Amendment Nos. 82 to 103 and Amendment No. 612 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 253 to 297 and 306 to 333 are by Shri Matilal Sarkar. Are you pressing your amendments?

SHRI MATILAL SARKAR (Mnipura): Yes, Sir.

Amendment Nos. 253 to 297 and 306 to 333 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 349 to 435 by Shri Prabhat Jha. He is not present.

Amendment Nos. 349 to 435 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 436 to 454 by Shri Shreegopal Vyas. He is not present.

Amendment Nos. 436 to 454 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 490 to 501 by Shri A. Vijayaraghavan. He is not present.

Amendment Nos. 490 to 501 were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 502 to 512 are by Shri N.K. Singh. Are you pressing your amendments?

SHRI N.K. SINGH (Bihar): Sir, having heard the persuasive speech of the Prime Minister, I beg the leave of this House to withdraw the amendments.

Amendments Nos. 502 to 512, were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put amendments 513 to 521 by Shri Raghunandan Sharma. Are you withdrawing the amendment or should I put them to vote?

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश): उपसभापति महोदय, 513 से 521 तक जो मेरे संशोधन हैं, मैं उनमें से एक संशोधन 516 को छोड़कर बाकी सब वापस लेना चाहता हूं। मैंने 516 संशोधन में आस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में उल्लेख किया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे इस संबंध में आगे जाकर आश्वासन देंगे, इस आशा के साथ मैं सभी संशोधन वापस लेता हूं।

Amendments (Nos. 513 to 521), were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendment Nos. 522 to 541 by Shri D. Raja. Are you pressing your amendments?

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 522 to 541) to vote.

Amendments (Nos. 522 to 541) were negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Amendments Nos. 542 to 611 by Dr. Akhlilesh Das Gupta. Are you pressing?

डा. अखिलेश दास गुप्ता: उपसभापति महोदय, हम लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री जी के भाषण को सुना है

और हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट्स सही थे, लेकिन जो उन्होंने आश्वासन दिया है, उसके आधार पर मैं अपने सभी अमेंडमेंट्स विदड्रा करता हूं।

Amendments (Nos. 542 to 611) were, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, I put to vote the Motion of Thanks to vote.

The question is:

"That an Address be presented to the President in the following terms- That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 22, 2010."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Demand to give approval to Indira Sagar Project across the Godavari River in Andhra Pradesh

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, the Polavaram project creates irrigation facility to an extent of 7.2 lakhs acres (about 2,91,262 ha) under its left and right canals in the upland areas of West Godavari, Krishna, East Godavari and Visakhapatnam district by diversion of 80 TMC of Godavari water to Krishna river.

The project will provide 23.44 TMC of water supply to industries in and around Vizag city and steel plant and drinking water supply to 28 lakhs people in 540 villages *en route* of the left and right main canal.

There will be generation of 960 MW of Hydro electricity and development of pisciculture and tourism apart from stabilisation of 10.5 lakhs acres (about 4,24,757 ha) under Godavari Delta.

There will be 171 lakhs of beneficiaries from this project. Therefore, I urge upon the Government to give final approval to the project.

Demand to take effective steps to get rid of the horrendous scenario of anaemia among children and women in rural India

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): The latest report of the Food Insecurity Situation in Rural India released on 20.02.2009, has revealed that calorie intake has remained stagnant in the last decade with about 13 per cent of the rural population consuming less than 1,890 Kcal/day. According to the composite index, prepared using indicators from the Census and National Family Health Survey, 2005- 06, Jharkhand has the highest level of food insecurity, followed by Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Bihar and Gujarat.